RNI No. MPHIN/2018/76422

बेबाकी के साथ...सच

माही की गूंज

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

सुविचार

एक समय में एक ही काम करो और पूरी निष्ठा ओर लगन से करो बाकी सब कुछ भुला दो।

स्वामी विवेकानंद जी

वर्ष-07, अंक - 50 (साप्ताहिक) खवासा, गुरूवार 11 सितम्बर 2025 पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए

सिस्टम पर चूहों का वार, सारी व्यवस्थाएं बेकार...!

पुरे सिस्टम को इस तरह से कुतरते चुहे।

झाबुआ जिले में अंतिम संस्कार के लिए संघर्षरत ग्रामीणों की तस्वीर।

माही की गूंज। संजय भटेवरा

इंदौर/झाबुआ। सरकारी दावों और हकीकत में जमीन आसमान का अंतर होता है, दावे बहुत कुछ किए जाते हैं लेकिन हकीकत उससे कोसों दूर ही रहती है। हम आजादी के अमृत काल में जीवन जी रहे हैं। लेकिन आज भी मूलभूत सुविधाओं के साथ ही अन्य व्यवस्थाओं के लिए जिस प्रकार आम आदमी का संघर्ष जारी है उससे तो यही कहा जा सकता है कि, क्या यही वह अमृत काल है जिसकी कल्पना आजादी के शहीदों ने की थी...?

पिछले दिनों प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के एक प्रतिष्ठित अस्पताल में दो नवजात शिशुओं को चूहों ने कुत्तर दिया जिससें वे काल के गाल में समा गए। और अपने पीछे सवाल छोड़ गए कि, इनका क्या कसुर था की वे जन्म लेते ही सिस्टम की अव्यवस्थाओं के चलते अपना जीवन काल का प्रारंभ ही नहीं कर सके। वहीं एक अन्य घटना झाबुआ जिले की थी जहां के ग्रामीण बारिश में अंतिम संस्कार के लिए संघर्ष करते नजर आ रहे हैं और ये दो घटनाएं ÷जीवन से लेकर मरण तक ÷की सरकारी व्यवस्थाओं की पोल खोल रही है और यह दर्शा रही है कि, मध्य प्रदेश में जीवन से लेकर मरण तक कुछ भी सुरक्षित नहीं है। जहां जीते जी चूहे कुतर देते हैं तो मरने के बाद अंतिम संस्कार भी सुरक्षित नहीं रहता है। वहीं ग्राम से लेकर महानगर तक में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा है।

लगातार आठ बार देश के सबसे ज्यादा स्वच्छ शहर का खिताब जीतने वाले इंदौर शहर में इस प्रकार की घटना यह साबित करती है कि, सबसे ज्यादा स्वच्छ शहर इंदौर में जब यह हाल है तो, अन्य शहरों के क्या हाल होंगे...?

यही नहीं इंदौर का एम वाय हॉस्पिटल शहर का प्रतिष्ठित सरकारी अस्पताल है और इस अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था और साफ सफाई पर प्रतिवर्ष 2 से 3 करोड रुपए खर्च किए जाते हैं। जिसकी जिम्मेदारी एक निजी कंपनी के हाथों में है और एम वाय अस्पताल प्रबंधन द्वारा इसके लिए नियमित भुगतान किया जाता है। और उसके बावजूद अस्पताल के इंसेंटिव केयर यूनिट में न केवल चूहे घूम रहे हैं बल्कि चूहों ने नवजात शिशुओं के अंगों को भी कुत्तर दिया, और बाद में इलाज के दौरान दोनों बच्चों की मौत हो जाती है। जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने कंपनी को जुर्माने के लिए एक लाख का नोटिस दिया। ऐसे में हर आम आदमी के मन में यही सवाल घूम रहा है कि, क्या दो नवजात शिशुओं की जान की कीमत महज 2 लाख रुपए हैं...?

आईसीयू जैसी यूनिट में चाक-चौबन्ध सफाई व 24 घंटे सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, व्यापक संसाधन मौजूद है। बावजूद इसके इस महत्वपूर्ण यूनिट में चूहों के घूमने की भनक किसी को भी नहीं लगी। यह न केवल गंभीर लापरवाही है वरन संवेदन हीनता की पराकाष्ठा भी है। यही नहीं घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन की लीपा -पोती की कार्रवाई अस्पताल की नियत और जवाब देही के प्रति उदासीनता को भी दर्शाती है।

इस घटना के बाद पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं के हालातो को समझ सकते हैं कि, पूरे सिस्टम में भ्रष्टाचार रूपी चूहे हर जगह मौजूद है और वो पूरे सिस्टम को उन दो मासूमो की तरह ही कुतर रहे हैं। अस्पताल की छतो से पानी टपकना, स्टाफ की कमी और संसाधनों के अलावा अब चूहे से सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। और सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि, उनकी स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी है और करोड़ों रुपए इन सेवाओं पर खर्च किए जा रहे हैं। यही नहीं झाबुआ जिले में अंतिम संस्कार के लिए संघर्षरत ग्रामीणों की तस्वीर भी यह बया कर रही है कि, सरकारी सिस्टम जिस हद तक असंवेदनशील बन चुका है और करोड़ों रुपए के निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार की खबरें आम बात है। जहां निर्माण कार्य शुभारंभ के बाद ही क्षतिग्रस्त हो जाता है। ऐसे में सरकार प्रत्येक गांव में श्मशान घाट निर्माण का दावा तो करती है लेकिन हकीकत कुछ और ही है ना तो श्मशान घाट है और ना ही वहां तक पहुंचने का रोड...!

15वें उपराष्ट्रपति बने सीपी राधाकृष्णन

नई दिल्ली, एजेंसी। सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने जीत दर्ज की। इस चुनाव में कुल 767 सांसदों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतगणना के दौरान 752 मत वैध पाए गए जबकि 15 मत अवैध करार दिए गए।

सीपी राधाकृष्णन को 452 मत मिले, जबकि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी को 300 मत ही प्राप्त हुए। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मंगलवार को संसद भवन में मतदान हुआ। मतदान प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले मतदान किया। मतदान शुरू होने से पहले सभी राजग सांसद सुबह साढ़े 9 बजे नाश्ते की बैठक में शामिल हुए। मुकाबला राजग के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बी. सुदर्शन रेड्डी के बीच था। संसद भवन में हुए इस मतदान में कुल 768 सांसदों ने भाग लिया। लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर संसद में कुल 788 सांसद होते हैं। वर्तमान में दोनों सदनों को मिलाकर 7 सीटें रिक्त हैं। इस प्रकार कुल 781 सांसदों को मतदान करना था, जिनमें से 13 सांसद मतदान में शामिल नहीं हुए। इनमें भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के 4, बीजू जनता दल (बीजद) के 7, अकाली दल के 1 और 1 निर्दलीय सांसद शामिल हैं। राजग के 427 सांसदों ने मतदान किया। इस चुनाव में राजग उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग भी हुई।

भारत-अमेरिका साझेदारी पर उम्मीदें, जल्द व्यापार समझौते की संभावना

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच घनिष्ठ मित्रता और प्राकृतिक साझेदारी पर जोर देते हुए कहा कि, दोनों देशों के बीच चल रही व्यापारिक वार्ताएँ भारत-अमेरिका साझेदारी की असीम संभावनाओं को खोलने का मार्ग प्रशस्त करेंगी। उन्होंने आशा जताई कि, इन चर्चाओं को शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री का यह बयान उस समय आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को महान देश बताते हुए व्यापार वार्ता जारी रखने की बात कही है। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन कर (टैरिफ) से जुड़े विवादों के बीच वार्ता फिलहाल रुक गई है। अमेरिकी दल को छठे दौर की वार्ता के लिए 25 अगस्त को भारत आना था, लेकिन ट्रंप द्वारा कर संबंधी घोषणाओं के बाद यह यात्रा टाल दी गई। नई तारीख की घोषणा अभी तक नहीं हुई है।

ट्रंप ने रूस से तेल की खरीद पर 25 प्रतिशत और भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत कर लगाया है। इसी बीच मोदी ने अपने वक्तव्य में कहा कि, भारत और अमेरिका घनिष्ठ मित्र और स्वाभाविक साझेदार हैं। उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि, हमारी व्यापारिक वार्ताएँ भारत-अमेरिका साझेदारी की असीम संभावनाओं को खोलेंगी। हमारी टीमें इन चर्चाओं को जल्द से जल्द पूरा करने में लगी हैं। मैं भी राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत करने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। हम मिलकर दोनों देशों के नागरिकों के लिए उज्ज्वल और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करेंगे।

प्रधानमंत्री के इस बयान को ट्रंप ने भी साझा किया। उन्होंने मोदी के सामाजिक मंच एक्स पर किए गए पोस्ट का चित्र लेकर अपने मंच 'ट्रुथ सोशल' पर साझा किया।

राहुल गांधी के दौरे पर हंगामा, मंत्री और भाजपाई कार्यकर्ता बैठे सड़क पर

रायबरेली।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के रायबरेली दौरे पर बुधवार को जमकर हंगामा हुआ। उनके काफिले को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह अपने समर्थकों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर धरने पर बैठ गए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राहुल वापस जाओ के नारे लगाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उनकी माता के खिलाफ की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी से माफी की मांग की।

धरना प्रदर्शन के चलते राहुल गांधी का काफिला कुछ समय तक रुका रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति संभालने की कोशिश की। इस बीच पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की और झड़प भी हो गई। बाद में पुलिस ने मंत्री व कार्यकर्ताओं को हटाया, जिसके बाद काफिला आगे बढ़ सका।

राहुल गांधी बुधवार सुबह दिल्ली से लखनऊ होते हुए रायबरेली पहुंचे थे। उनका यह दौरा दो दिनों का है, जिसमें वे पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उधर, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस घटनाक्रम के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं।

मध्यप्रदेश शांति का टापू, लोकहितैषी नीतियाँ मददगार - सीएम

कोलकाता।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को कोलकाता में आयोजित निवेशकों की बैठक में प्रदेश की संभावनाओं को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि, मध्यप्रदेश आज देश का शांति का टापू है, जहां उद्योग और व्यापार के लिए उपयुक्त वातावरण उपलब्ध है।

सीएम डॉ. यादव ने निवेशकों से सीधे संवाद करते हुए बताया कि प्रदेश सरकार ने उद्योगों के लिए सरल नीतियाँ लागू की हैं उन्होंने कहा कि सरकार की लोकहितैषी नीतियाँ न केवल बड़े उद्योगों के लिए बल्कि छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए भी मददगार साबित हो रही हैं।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, संसाधनों और तेज़ी से विकसित हो रहे औद्योगिक क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सड़क, रेल और वायु मार्ग से देश के हर हिस्से से जुड़ा हुआ है। यह निवेशकों के लिए एक बड़ा लाभ है।

कभी न भूलने वाली तारीख पर दस साल बाद मुख्यमंत्री होंगे जनता के बीच

मुख्यमंत्री के दौरे से पहले किसान आंदोलन को रोक पाने में असफल रहा प्रशासन

माही की गूंज, पेटलावद। राकेश गेहलोत

पेटलावद के इतिहास में दर्ज तारीख 12 सितम्बर दस साल बाद फिर से चर्चा में है। आज से ठीक दस साल पहले पेटलावद में सब कुछ सामान्य था सभी सुबह-सुबह, अपने-अपने कार्य में जुटे थे। बच्चे स्कूलों के लिए निकल पड़े थे, मजदूर अपने कार्य पर जाने के इंतजार में खड़े थे, मार्ग से निकलने वाले सुबह के नाश्ते के लिए पेटलावद के थांदला रोड पर स्थित होटलों पर नाश्ता करने के लिए रुके थे। सुबह की साढ़े आठ बजी होगी और अचानक थांदला रोड की एक दुकान में आग लगने की जानकारी सामने आई और देखने के उत्साह में लोग उस स्थल की ओर दौड़ पड़े जो की एक नेसर्गिग प्रक्रिया है। तथा लोग कुछ समझ पाते कि आग कौनसे गंभीर स्थल पर लगी है, आग को रोकने के प्रयास में जुट कर दुकान मालिक राजेंद्र कासवा को सूचना कर बुलाया। पुलिस थियोरी के अनुसार दुकान मालिक वहा पहुंचा और इससे पहले की वो लोगो को बता सके की यहां जिलेटिन की ब्लासिंटग राड और सेकड़ो टन कृषि खाद पड़ा है, एक जोरदार धमाका होता है और सब कुछ तबाह हो जाता है। लोगो के अंग सड़क पर बिखरे पड़े, सेकड़ो घायल अपने ही अंगों को समेटे दिखे। देखते ही देखते 79 लोग मौत के घाट उतर गए और सेकड़ो लोग घायल अस्पताल पहुंचाए गए। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में आक्रोश पनपा और लोग सड़कों पर उतर कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने पर आमादा हो गए। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने मामले की गंभीरता समझी और बिना देर किए अगले ही दिन यानी 13 सितंबर को पेटलावद पहुंच कर प्रदर्शन कर रहे लोगो के साथ सड़क पर बैठ कर पीड़ितों से न्याय करने और ब्लास्ट के जिम्मेदार लोगो पर कड़ी कार्रवाई के आश्वासन दिया। साथ ही पीड़ित परिवार को सहायता राशि और एक सदस्य को नोकरी देने के आश्वासन के साथ पूरे मामले को शांत करने का काम किया। दिन ,तारीख, समय निकलता गया सहायता राशि को छोड़ कर मुख्यमंत्री का कोई वादा पूरा नहीं हुआ। न ही सभी मृतकों के परिजनों को नोकरी मिल पाई न ही ब्लास्ट के जिम्मेदारो को सजा।

पुलिसिया लापरवाही से दर्ज प्रकरण और जिम्मेदारो के नाम पर सरकार को बचाने के प्रयास में ऐसा केश तैयार हुआ जो न्यायालय में औंधे मुंह गिरा और पुलिस द्वारा बनाए गए सभी आरोपी बरी होने के साथ मुख्य आरोपी राजेंद्र कासवा को ब्लास्ट में मृतक मान लिया गया। उसके बाद से ही ब्लास्ट पीड़ितो के लिए 12 सितम्बर की तारीख एक मनहूस दिन की तरह बन कर रह गई। जब भी ये तारीख आती है अपनो को खोने वाले यहा आकर आसू बहा कर चले जाते है। क्योंकि ब्लास्ट के बाद उनका जीवन समय के साथ-साथ पटरी पर आ गया। ब्लास्ट में कई घायल आज भी आधी-अधूरी जिंदगी जीने पर मजबूर है। इन दस सालो के शुरुआत के कुछ सालो में इस तारीख पर राजनीति होती रही। पक्ष-विपक्ष के नेता एक-दूसरे पर हमला करते दिखाई दिए जो समय के साथ खुद ही गायब हो गए, कोई मुख्यमंत्री दोबारा इस तारीख पर यहा लोट के नही आया। अब ठीक दस साल बाद प्रदेश के नए बने मुख्यमंत्री मोहन यादव इस 12 सितंबर को पेटलावद में एक आयोजन में शामिल हो रहे है। जिसके चलते ये तारीख और पूरा घटना क्रम एक बार फिर चर्चा में है और एक बार फिर ब्लास्ट पीड़ितो के जख्म फिर से हरे और गहरे होकर उभर गए है। उम्मीद है कि, मुख्यमंत्री मृतकों की याद में बने श्रद्धांजलि चौक पर रुकने की रस्म अदायगी न करते हुए एक बार उन ब्लास्ट पीड़ितो से मुलाकात कर उनसे उनका हाल और सरकारी मद्दत की स्थिति जानेंगे।

मुख्यमंत्री के आगमन हेतु जमकर प्रशासनिक तैयारिया।

कई चुनौतियां मुख्यमंत्री यादव के सामने, किसान आंदोलन को नही रोक पाई मंत्री भूरिया

झाबुआ जिले में सबसे सक्रिय विकास खंड पेटलावद को माना जाता है। यहा हर तरह के मुद्दे छाए रहते है फिर वो चाहे भ्रष्टचार के हो या भू-माफियाओं के, या राजनीति के यहा हमेशा चर्चा का विषय रहा है। ब्लास्ट एक बहुत बड़ा विषय मुख्यमंत्री के लिए तो है ही, साथ ही कन्यादान योजना की राशि जो की लगभग 250 हितग्राहियों के खातों में डालना थी, खुद मुख्यमंत्री आयोजन में शामिल होकर नव विवाहित जोड़े के घर पहुंचने से पहले राशि खातों में आने की बात मंच से कह चुके है ,06 माह बाद भी एक हितग्राही का भुगतान नही हुआ है। वर्तमान में किसानो को सरकार ने फसल बीमा की राशि का भुगतान किया है। पेटलावद विधानसभा में सबसे ज्यादा 19 करोड़ 29 लाख की राशि किसानो को भुगतान होना प्रशासन ने बताया है। इसके बाद भी यहां के किसान फसल बीमा राशि नही मिलने, कम मिलने और कई ग्राम पंचायते योजना से छूट जाने को लेकर सड़क पर उतरने को उतारू है। केबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया खुद की विधानसभा में हुई इतनी बड़ी राशि के भुगतान के बाद भी इसको भुनाने में असफल साबित हुई। किसान यूनियन एक बार अनुविभागीय अधिकारी के कार्यकाल में धरना दे चुके, तो दूसरी बार बीएसएनएल के टावर पर चढ़ने का प्रयास कर चुके है। बाबजूद इसके मंत्रीजी, किसानो और प्रशासन की खीच तान में मध्यस्ता कर मामले को समाप्त नही कर पाई। जिसके चलते मंगलवार को मुख्यमंत्री के दौरे से पहले किसान सड़क पर उतरने को मजबूर हो गए और रायपुरिया-राजगढ़ मार्ग पर चक्काजाम कर मार्ग को घंटो बाधित किया। किसान यूनियन ने मंत्री के जिले में होने के बाद भी उनको बुलाने तक की मांग तक नही की और प्रशासनिक अधिकारियों, बीमा कम्पनी के अधिकारियो के साथ जनपद अध्यक्ष रमेश सोलंकी ने मोर्चा संभाल कर आंदोलन को खत्म करवाया।

साथ ही भ्रष्टाचार का मुद्दा भी वर्तमान में गहराया हुआ है। जनपद पंचायत पेटलावद में सेकड़ो शिकायते भ्रष्टचार की आ रही है। वही नगर में बन रहे चार करोड़ से अधिक लागत के ब्रिज निर्माण में घटिया सामग्री और लापरवाही सामने आ रही है। जिले में पेयजल हेतु गाव-गाव में किए जा रहे कार्य में बड़ा भ्रष्टचार का मुद्दा भी सुर्खियो में है।

लाडली बहनों को होगा किश्त का भुगतान, नए नाम नही जुड़ने से निराशा

12 सितंबर को पेटलावद आ रहे मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 28 वी किश्त का भुगतान कर सकते है। वही योजना में लगातार कई हितग्राही के नाम किसी न किसी कारणों से कटने की जानकारी आती रही है लेकिन योजना के शुरू होने के बाद से नए नामो को जोड़ने का कार्य सरकार की ओर से नही किया गया। जिससे योजना के लाभ से वंचित लाडली बहनों में निराशा है और उनकी मांग है कि, नए नाम जोड़ने के लिए आवेदन लेने का कार्य शुरू करना चाहिए। विपक्ष में लगातार नए नाम नही जोड़ने को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगा कर धीरे-धीरे योजना बंद करने का आरोप लगा रही है।

हादसों की मौतों में चौथा और दुर्घटनाओं में प्रदेश का नंबर दूसरा, तेज रफ्तार में हुए हादसों में मध्यप्रदेश प्रथम

माही की गूंज, झाबुआ।

सरकार समस्या के समाधान पर सोचने से परहेज करती दिखाई दे रही है, क्योंकि आंकड़ो के अनुसार और रिपोर्ट के अनुरुप देश हादसों का देश बनता जा रहा है और इन हादसों में मरने वालों से देश एक प्रकार की आपदा का परिचायी हो सकता है। यदि अभी भी सरकार सड़क परिवहन या फिर यातायात के प्रति सजग नहीं हुई और अपनी जनता को सजग नहीं किया तो हादसे और इन हादसों में मरने वालों की संख्या प्रतिवर्षानुसार बढ़ती जाएगी जो की देश के लिए एक आपदा का रुप ले लेगी। हाल ही में केंद्रीय सडक् परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की है जो कि देशभर में वर्ष 2023 में हुए सडक् हादसों की विस्तृत रिपोर्ट है।

इस रिपोर्ट के अनुसार मध्यप्रदेश में सड़को की बदहाली और सड़क सुरक्षा व्यवस्था की बदइंतजामी खुलकर सामने आई है। रिपोर्ट बताती है हादसों में पहले नंबर पर तमिलनाडु है और दूसरे नंबर पर मध्यप्रदेश है। जहां लाखों हादसे नियमों के तोड़ने पर हो जाते हैं और 60 प्रतिशत दुर्घटनाएं जिनमें मौके पर ही मौत जीवन को लील जाती है। 20 प्रतिशत मौतें चिकित्सा सुविधा के अभाव में अस्पताल पहुंते-पहुंचे ही हो जाती है। वहीं 20 प्रतिशत मौतें उपचार के दौरान हो जाती है।

इस रिपोर्ट के अनुसार देशभर में 2023 में 4 लाख 80 हजार 583 सड़क हादसे हुए है इन हादसों में 1 लाख 72 हजार 890 लोगों की मौत हुई है और 4 लाख 62 हजार 825 लोग घायल हुए है। घायलो में 50 प्रतिशत से ज्यादा गंभीर घायल है। प्रदेश में हो रहे हादसों के कारण को भी दर्शाया गया है। रिपोर्ट में तेज गति के कारण होने वाली दुर्घटना में मध्यप्रदेश अव्वल नंबर पर है। वहीं ट्रैफिक नियम तोड़ने के कारण सबसे ज्यादा दुर्घटना मध्यप्रदेश में हो रही है।

विशेषज्ञो द्वारा वर्ष 2020 से लेकर 2023 तक के हादसों के आंकड़ो का विश्लेषण किया गया, जिसमें सामने आया है, शाम 6 बजे से रात 9 बजे के मध्य सबसे ज्यादा हादसे हुए है। 2023 में इस समयावधि में 99 हजार 945 हादसे हुए जो कि कुल हादसों का 20.8 प्रतिशत है और ऐसे हादसों में मृत्यु को प्राप्त होने वाले सबसे ज्यादा दो पहिया वाहन चालक है। 2023 में 7 हजार 591 दो पहिया सवारो की मौत हुई है और पैदल चलने वालों की संख्या 4 हजार 604 और 1 हजार 593 कार सवारों की दुर्घटना में मौत हुई है। ट्रैफिक नियम नहीं मानने पर 44 हजार से ज्यादा हादसे हुए।

इन आंकड़ो और रिपोर्ट के अनुसार लोगों ने नियम तोड़े तभी वे दुर्घटना के शिकार हुए। लोगों ने जल्दबाजी में भी दुर्घटना को निमंत्रण दिया जिसके कारण उनको और उनके परिवार को ऐसी हानि पहुंची जिसकी क्षति पुर्ति करना असंभव है।

लोग, नियमों का पालन क्यों नहीं करते हैं? क्या इस विषय पर कभी कोई गंभीर स्तर की चर्चा की गई, जिसकी रिपोर्ट पेश की गई हो। इस विषय पर क्या कभी सामाजिक स्तर पर कोई पहल की गई हो। इस विषय पर क्या कभी राजनीतिक विचार धारा के प्रभावी लोगों द्वारा मंच से लोगों को समझाईश दी गई। पुलिस द्वारा यातायात सप्ताह मनाने के अलावा दुर्घटना या हादसों को रोकने के कोई उपाय किए। आरटीओ विभाग द्वारा लाईसेंस जारी करते समय वाहन चालक का परिक्षण या उसके नियमों की जानकारी की कोई परिक्षा ली...? इन सभी प्रश्नवाचक वाक्यों का उत्तर एक शब्द में दिया जा सकता है। नहीं।

सरकार सड़क हादसों को गंभीरता से नहीं लेगी तो यह समस्या बढ़ती ही चली जाएगी। जनसंख्या वृद्धी होती जा रही है, लोग बढ़ रहे हैं, शाम को सभी लोगों को ऑफिस से घर जाने की जल्दी होती है और उसी जल्दी में वो नियम तोड़ते हुए हादसों का शिकार हो जाते हैं।

रिपोर्ट में दर्शाए गए समस्त कारणों की गहराई में जाए तो ज्ञात होगा कि, व्यक्ति यातायात के सम्बंध में जागरुक नहीं है। उसे अपने अहंकार और अपनी मर्जी का काम करने में ज्यादा संतुष्टी मिलती है और इस संतुष्टी को वह वाहन चलाते समय भी पाना चाहता है जो की नियमानुसार सही नहीं है। यदि किसी बाइक वाले से कोई आगे निकल जाता है तो वह भी गति तेज कर उसका पीछा करके उसे पीछे करने की कोशिश करता है और कभी-कभी इसी कोशिश में वह दुनिया को पीछे छोड़ कर चला जाता है।

रिंकेश बैरागी

पुलिस वर्षभर में सात दिवस का यातायात सप्ताह मनाती है जिसमें वह अधिकतर विद्यालयो में जा-जा कर विद्यार्थियों को यातायात के सम्बंध में जागरुक करती है। यह एक प्रकार से अच्छी बात है मगर क्या इन सात दिनों में इतनी जागरुकता आ जाती है कि, लोगों में यातायात की समझ आ जाए। अगर ऐसा होता तो केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट दुर्घटना के इतने भयानक आंकड़ो को प्रस्तुत नहीं करती न ही हादसों की विस्तृत जानकारी देकर हो चुके हादसों का विश्लेषण नहीं करती।

हादसों को रोकने के लिए समझाईश की टोली को सक्रिय होकर वाहन चालको को यातायात के नियमों के बारे में बताना होगा। सामाजिक संगठनों को सामने आ कर एक मुहिम के रुप में कार्यक्रमों को आयोजित करना होगा। जिसमें समाज के सभी वर्गों की उपस्थिति को अनिवार्य करना होगा। तब कहीं यातायात के सम्बंध में जागरुकता फैलेगी और संभवतः सड़कों पर होने वाले हादसों में कुछ कमी होगी। वहीं सरकार को यातायात प्रबंधन और परिवहन के नियमों को पाठ्यक्रम में शामिल करना होगा जिससे भावी पीढ़ी पहले ही इस आपदा से सतर्क हो जाए और भारत देश में होने वाले हादसे कम हो और युवा सड़को पर सुरक्षित रहे।

लापता का शव मिला

माही की गूंज, थांदला।

पिछले दिनों थांदला में लगातार बारिश का दौर जारी था और पद्मावती नदी अफलातून बह रही थी। वही थांदला के दो युवक 5 तारीख से लापता थे जिसमें से एक युवक का शव पद्मावती नदी में मिला। कुछ लोगों को खबर लगी थी कि, तीन युवक नदी में गिरे हैं जिसकी सूचना पुलिस को मिली। पुलिस ने रात भर उन्हें ढूंढा लेकिन वह नहीं मिले और दिनांक 5 सितंबर की रात को घर से लापता थे दोनों युवक के पिता ने 6 सितंबर को थाने पहुंचकर गुमशुदगी की सूचना दर्ज कराई थी। इसी तारतम में थाना क्षेत्र के अंतर्गत रविवार को एक युवक का शव मिला। जिसकी शिनाख्त आकाश पिता खुशहाल खराड़ी उम्र 17 वर्ष निवासी राजापुरा थांदला के रूप में हुई।

वहीं आकाश के साथ उसके मामा का लड़का जितेन्द्र पिता नाथु उम्र 29 वर्ष निवासी राजापुरा थांदला लापता था।

श्रीमद भागवत कथा का समापन

माही की गूंज, पारा। ग्राम के श्री राम मंदिर प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। श्री राम मंदिर के पुजारी कमलेश दास बैरागी में बताया कि, श्री भागवत कथा पारा ग्राम के पंडित संजय शर्मा द्वारा कथा का वाचन किया गया। साप्ताहिक भागवत कथा में नगर की धर्म प्रेमी जनता पुरुष-महिलाएं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कथा आयोजन में ग्राम की महिलाओं की अहम भूमिका रही।

प्रसंगों पर स्वांग रचा

जारी कथा के दौरान कथा में जब-जब महत्व पूर्ण प्रसंग आए तब तब महिलाओं तथा बच्चो ने प्रसंग का स्वांग रच कर आयोजन पर चार चांद लगा दिए। जैसे कृष्णा राधा नकल स्वरूप रुक्मणी विवाह 56 भोग प्रसादी भी चढ़ाई गई । रविवार को चंद्र ग्रहण होने के कारण गांव के मंदिरों के पट बंद कर दिए गए। एक दिन विलंब के बाद भागवत कथा का साय 4:00 बजे समापन कर भागवत गीता का व ट्रैक्टर पर बनी झांकी में सवार प. संजय शर्मा का नगर भ्रमण हुआ। नगर भ्रमण के दौरान गांव के गली चौराहे पर नागरिकों द्वारा भव्य पुष्प की वर्षा की गई व गांव के चौराहे पर महिलाएं व युवाओ ने झमाझम बारिश के बीच गरबा नृत्य किया गया। शोभा यात्रा पुंनः श्री राम मंदिर प्रांगण पहुंची। बाद महाआरती उतारी गई प्रसादी वितरण कर कार्यक्रम का समापन हुआ।

सांवरिया के दर्शन करने यात्री पैदल रवाना

माही की गूंज, सारंगी।

राजस्थान मंडफिया में प्रसिद्ध मंदिर श्री सांवरिया सेठ के दर्शन के लिए 20 सदस्यों का का दल मंगलवार सुबह 7 बजे पैदल रवाना हुआ। भक्तों ने पैदल यात्रा शुरू करने से पहले ग्राम के लक्ष्मी नारायण मंदिर, माताजी मंदिर, बस स्टैंड अंबे माताजी मंदिर, खेड़ापति हनुमान जी मंदिर के दर्शन कर पैदल रवाना हुए । पैदल जा रहे सभी भक्तों का बस स्टैंड माताजी मंदिर पर जनपद सदस्य रजनीश पाटीदार, सत्यनारायण अग्रवाल, संजय उपाध्याय, पत्रकार साथी सुरेश परिहार, धर्मेंद्र प्रजापत एवं ग्रामवासियों द्वारा हार पहना कर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया एवं मंगलमय यात्रा की शुभकामनाएं दी। पैदल यात्री जितेंद्र पाटीदार ने बताया, हमारी यह पैदल यात्रा सारंगी से सांवरिया जी मंदिर तक

नेशनल लोक अदालत के प्रचार-प्रसार हेतु वाहन को हरी झंडी

माही की गूंज, झाबुआ।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ के तत्वाधान में 13 सितम्बर को आयोजित होने वाली वर्ष की तीसरी नेशनल लोक अदालत के लिए प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्रीमती विधि सक्सेना के द्वारा प्रचार-प्रसार वाहन को हरी झंडी दिखाकर न्यायालय परिसर झाबुआ से रवाना किया गया।

इस अवसर पर प्रधान जिला न्यायाधीश श्रीमती विधि सक्सेना ने कहा कि, लोक अदालत हमारे न्याय तंत्र की वह व्यवस्था है, जिसके माध्यम से आमजन अपने विवादों का त्वरित, सुलभ और निःशुल्क समाधान पा सकते हैं। इसमें न तो लम्बी अदालती प्रक्रिया की जटिलता होती है और न ही अधिक खर्च का बोझ। पक्षकार आपसी सहमति से अपने विवाद का निपटारा कर सकते हैं और उस निर्णय को न्यायालय की डिक्री के समान मान्यता प्राप्त होती है। यह प्रचार वाहन जिले के विभिन्न स्थानों पर जाकर आम नागरिकों को लोक अदालत के महत्व और उपयोगिता से अवगत कराएगा। अधिक से अधिक संख्या में अपने लंबित प्रकरणों को लोक अदालत के माध्यम से निपटाने का प्रयास करें। राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य केवल विवादों का समाधान करना ही नहीं, बल्कि समाज में सौहार्द, आपसी समझ और मेल-मिलाप की भावना को बढ़ावा देना भी है।

इस अवसर पर लोक अदालत के प्रभारी अधिकारी/विशेष न्यायाधीश विवेक सिंह रघुवंशी, प्रथम जिला न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार शर्मा, द्वितीय जिला न्यायाधीश सुभाष सुनहरे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नितिन कुमार मुजाल्दा, न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती सरोज बाला मुजाल्दा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव शिव कुमार डावर, जिला विधिक सहायता अधिकारी जयदेव माणिक, अभिभाषक संघ झाबुआ के अध्यक्ष दीपक भण्डारी, अधिवक्तागण, कर्मचारीगण एवं आमजन उपस्थित रहें।

नेपाल हिंसा की लपटें भारतीय सीमा तक, कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ और आगजनी, हालात तनावपूर्ण

पिथौरागढ़।

नेपाल में जारी हिंसक आंदोलन का असर भारतीय सीमा तक पहुँच गया है। झूलाघाट और धारचूला से लगे नेपाली क्षेत्र दार्चुला और बैतड़ी में भी उग्र प्रदर्शन हुए। दार्चुला में प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस तथा एमाले कार्यालय में तोड़फोड़ की और आगजनी की घटनाएँ सामने आईं। इसके बाद पूरे इलाके में तनाव गहराया हुआ है।

झूलाघाट अंतरराष्ट्रीय पुल से लगभग पच्चीस किलोमीटर दूर बैतड़ी के साहिलेक बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। यहाँ युवाओं ने सामाजिक माध्यम पर लगाए गए प्रतिबंध के विरोध में प्रदर्शन किया।

धारचूला से लगे दार्चुला क्षेत्र में भी लोग बहुमुखी परिसर में एकत्र हुए। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने दार्चुला बाजार में जुलूस निकाला और प्रमुख ज़िलाधिकारी कार्यालय तक पहुँचकर पत्थरबाजी की। भीड़ उग्र हो गई और कांग्रेस तथा एमाले-माओवादी कार्यालयों में तोड़फोड़ की।

नेपाल पुलिस और सशस्त्र प्रहरी बल की संयुक्त टीम घटनास्थल पर पहुँची, लेकिन उग्र भीड़ को नियंत्रित करने में नाकाम रही।

गौरतलब है कि भ्रष्टाचार और सामाजिक माध्यम पर प्रतिबंध को लेकर भड़का जनाक्रोश लगातार दूसरे दिन भी नेपाल में हिंसा का रूप लेता रहा। हालात इतने बिगड़े कि भीड़ ने संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और सर्वोच्च न्यायालय तक को आग के हवाले कर दिया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के निजी आवास सहित कई मंत्रियों और नेताओं के घरों एवं दफ्तरों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएँ हुईं। जनाक्रोश के दबाव में अंततः प्रधानमंत्री ओली को इस्तीफा देना पड़ा।

महागठबंधन में ओवैसी की पार्टी को शामिल करने का निर्णय लालू करेंगे

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर दिल्ली में मंगलवार को कांग्रेस की बैठक हुई। बैठक के बाद बिहार प्रभारी कृष्णा अलावरू ने बताया कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने महागठबंधन में शामिल होने को लेकर राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखा है। इस पर उन्होंने कहा कि यह पत्र लालू को लिखा गया है, इसलिए इस पर वही स्पष्ट करेंगे। कांग्रेस का इससे कोई संबंध नहीं है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि पशुपति कुमार पारस की पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) को महागठबंधन में शामिल किए जाने पर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि इस दिशा में बातचीत सकारात्मक है और बहुत जल्द इस पर औपचारिक घोषणा हो सकती है।

सीटों के बंटवारे पर अलावरू ने कहा कि कांग्रेस ने अपनी सूची राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दी है। इस मुद्दे पर समन्वय समिति में विचार-विमर्श जारी है। उन्होंने भरोसा जताया कि 15 सितम्बर तक सीट बंटवारे पर अंतिम निर्णय हो जाएगा।

अलावरू ने यह भी कहा कि कांग्रेस को जितनी भी सीटें मिलेंगी, वह उसमें कोई आपत्ति नहीं करेगी। अभी तक की बातचीत सकारात्मक रही है। महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरेगा और कोई विवाद नहीं होगा। अलावरू के बयानों से साफ है कि कांग्रेस सीट बंटवारे में लचीलापन दिखाने के मूड में है। वहीं, ओवैसी की पार्टी को महागठबंधन में जगह देने या न देने का फैसला अब लालू यादव करेंगे। इससे यह भी स्पष्ट है कि कांग्रेस के संकेत बताते हैं कि सीट बंटवारे और संभावित सहयोगियों को लेकर 15 सितम्बर तक तस्वीर साफ हो जाएगी।

अब कनाडा ने खारिज कर दिए 80 प्रतिशत भारतीय छात्रों के वीजा

नई दिल्ली।

कनाडा और अमेरिका भारतीय छात्रों के लिए पसंदीदा देश रहे हैं, जहाँ वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंबे समय से संघर्ष करते रहे हैं। लेकिन इन दोनों देशों के खराब बर्ताव और भारतीय छात्रों के प्रति उदासीन रवैये की वजह से अब छात्रों का रुझान जर्मनी की ओर बढ़ रहा है। जर्मनी शीर्ष पसंदीदा देश बनकर उभरा है। इसी कारण कनाडा अब सिर्फ 9 प्रतिशत छात्रों की पहली पसंद बनकर रह गया है।

भारतीय प्रवासी छात्रों और एच-1बी वीज़ा धारकों पर हाल के दिनों में अमेरिका की ट्रंप सरकार की कठोर कार्रवाई के बाद अब उसके पड़ोसी देश कनाडा ने भी भारत को करारा झटका दिया है। कनाडा ने वर्ष 2025 में 80 प्रतिशत भारतीय छात्रों के वीज़ा आवेदन रद्द कर दिए, जो पिछले दस वर्षों में सबसे अधिक है।

आँकड़ों के अनुसार, एशिया और अफ्रीका के अन्य देशों के छात्रों के वीज़ा आवेदन भी खारिज किए गए हैं लेकिन भारतीय छात्र अधिक थी। सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। कनाडा के इस कदम का असर वहाँ के महाविद्यालयों में नामांकन पर भी पड़ा है।

कनाडा सरकार के आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024 में कनाडा ने केवल लगभग 1.88 लाख नए भारतीय छात्रों को ही प्रवेश दिया, जबकि दो वर्ष पहले तक यह संख्या दोगुनी से भी

भारत समेत दुनिया भर के छात्रों के लिए कनाडा इसलिए अपना दरवाज़ा बंद कर रहा है क्योंकि वहाँ बड़े पैमाने पर आवासीय सुविधा की कमी है। इसके अलावा बुनियादी ढाँचे पर दबाव है और स्थानीय राजनीति की वजह से भी कनाडा को यह कदम उठाना पड़ा है।

कनाडा ने छात्रों को वीज़ा देने के नियम भी सख्त कर दिए हैं। अब आवेदन करने वाले छात्रों को पहले की तुलना में अधिक वित्तीय प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। यानी अब उन्हें 20 हज़ार कनाडाई डॉलर के काग़ज़ दिखाने होंगे। इसके अलावा विस्तृत अध्ययन योजना और भाषा परीक्षा के परिणाम भी देना अनिवार्य कर दिया गया है।

व्यवस्था पर कटाक्ष

आबकारी विभाग बना शराब ठेकेदार का अघोषित पार्टनर

सरकार, आबकारी विभाग को घोषित करे वैध पार्टनर, ताकि अवैध शराब बिक्री पर कार्रवाई के लिए शराब ठेकेदार के इशारे का इंतजार न करना पड़े

माही की गूंज, झाबुआ।

लगातार फलते-फूलते अवैध शराब के व्यवसाय को रोकने के लिए सरकार के सारे प्रयास नाकाफी साबित हो रहे है और अवैध शराब की बिक्री दिन दुगनी, चार चोगनी प्रगति कर रही है। जिससे सरकार के नशे के विरुद्ध चल रही मुहिम को करारा झटका लग रहा है। जिसका जिम्मेदार मुख्य रूप में मादक पदार्थो की तस्करी और अवेध बिक्री पर रोक लगाने का काम आबकारी विभाग का है। वर्तमान में आबकारी विभाग की स्थिति अवैध शराब को लेकर ऐसी हो चली है कि विभाग, लाइसेंसी शराब ठेकेदार के रूप में कार्य कर रहा है और केवल इतना ही कार्य करता है जितना ठेकेदार की ओर से इशारा होता है।

अघोषित पार्टनर बना आबकारी विभाग

जिस तरह से शराब ठेकेदार द्वारा अवैध रूप से खुलेआम अवैध शराब जगह-जगह काउंटर खोले गए है और उनको पूरा सरक्षण आबकारी विभाग का मिलता है, जैसे आबकारी विभाग, सरकार का उपक्रम न होकर शराब ठेकेदार का पार्टनर ही हो। किस की अवैध शराब पकड़ना है, किसकी नही ये भी क्षेत्र का शराब ठेकेदार तय करता है। आबकारी विभाग का ट्रेक रिकॉड अवैध शराब के दर्ज मामलों को देखा जाए तो पता चलेगा कि, ज्यादातर मामले 15 से 20 क्वाटर का बना कर खाना पूर्ति की जाती है। इसमें से ज्यादातर तो रिकॉड खानापूर्ति के लिए अवैध शराब विक्रेताओं को छापामारी कर पकड़ने की जगह उनको ही गिने-चुने शराब के क्वार्टर लेकर कार्यालय पर बुला कर अन्य किसी के नाम से जिनका शराब व्यवसाय से दुर-दुर तक कोई लेना-देना ही नही रहता है उनके नाम से प्रकरण बना कर अवैध शराब के नाम पर की जाने वाली कार्रवाई की इतिश्री कर दी जाती है।

पकड़ी गई अवैध शराब ठेकेदार की दुकान की शराब के बेच नंबर से नहीं हुई जांच

कहने को तो अवैध शराब के ढेरो प्रकरण आबकारी विभाग ने बना रखे है और हर प्रकरण में शराब जप्त होती है। सभी शराब की बोतलो पर होलोग्राम और बेच नंबर होता है। सारे प्रकरण में दर्ज शराब के होलोग्राम व बेच नम्बर की शराब किस ठेकेदार के माध्यम से अवैध शराब, दुकानदार तक पहुंची है इसकी जानकारी जुटाई जा सकती है। लेकिन आबकारी की ओर से अवैध शराब का प्रकरण न्यायालय में पेश कर मामले की इतिश्री कर ली जाती है। आबकारी विभाग की कार्य प्रणाली पुरी तरह इस कदर दूषित हो चुकी है कि, अवैध शराब की सूचना पर कोई भी कार्रवाई से पहले सूचना क्षेत्र के ठेकेदार तक पहुंच जाती है। जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों से अवैध शराब की सूचना पर ठेकेदार के लोग पुलिस और आबकारी से पहले पहुंच जाते है।

आबकारी विभाग को वैध पार्टनर घोषित करे सरकार...!

अवैध शराब पर होने वाली कार्रवाई और खेरची लाइसेंसी शराब ठेकेदार द्वारा थोक में वह भी गाडियो से बेची जा रही अवैध शराब पर कार्यवाई व सरकारी नियमो से विक्रय हो इसकी देख-रेख आबकारी को करना होती है। जबकि यह विभाग ठेकेदार द्वारा अवैध शराब खुले आम दो पहिया और चार पहिया से शराब बिक्री करवा रहा है नतिजन आबकारी विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नही की जाती है। आबकारी विभाग की कार्य प्रणाली पूरी तरह से सरकार की शराब नीति के विरुद्ध काम कर रही है और अवैध शराब विक्रेताओं को सरक्षण मिल रहा है। ऐसी स्थिति में सरकार को, आबकारी विभाग को शराब ठेकेदारों का वैध पार्टनर घोषित कर दे ताकि विभाग को शराब ठेकेदारों के इशारों पर काम नही करना पड़े और स्वविवेक से कार्रवाई कर सके।

आखिर नाबालिग छात्र छात्रावास कक्ष में क यों लटका फंदे पर ...?

माही की गूंज, झाबुआ।

खवासा चौकी अंतर्गत ग्राम रन्नी व बामनीया चौकी के अंतर्गत मोईचारण के नाबालिक प्रेमी युवक-युवती की आत्म हत्या का वास्तविक कारण अभी तक सामने नहीं आया है। वहीं दूसरी ओर जिला मुख्यालय पर स्थित जनजातीय सीनियर बालक छात्रावास के कक्ष नंबर 10 में सोमवार को 17 वर्षीय नाबालिक 11वी का छात्र करण पिता वीरेंद्र भाभर निवासी बोचका ने फंदे पर लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उक्त घटना के बाद छात्र के ग्राम के साथ जिला मुख्यालय से लेकर जिले में यही चर्चा होने लगी कि, आखिर नाबालिक छात्र करण ने छात्रावास कक्ष में फंदे पर लटककर आखिर क्यों अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली...?

कही न कहीं यह सवाल गलत भी नहीं है। क्योंकि जहां छात्र के परिजन कह रहे हैं कि, करण को किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं था, न ही किसी प्रकार का कोई विवाद था। करण शुक्रवार से रविवार 3 दिन की छुट्टी में घर पर पूरी तरह से खुश था। रविवार शाम को करण छात्रावास में आया था। वही यह बात सामने आ रही कि, करण ने छात्रावास में आने के बाद शाम को भोजन नहीं किया था और वह थोड़ा उदास भी था। एक तरफ परिजन खुश होने की बात करण के प्रति कर रहे हैं, तो दूसरी ओर छात्रावास में शाम का भोजन नहीं कर थोड़ा उदास होने की बात होने लगी है। यह दोनों बात कही मेल न खाकर इसमें कई कारण छुपे होने का अंदेशा लगाया जा रहा है।

वहीं परिजन आक्रोशित होकर करण की हत्या किए जाने व छात्रावास व्यवस्था पर आरोप लगा रहे हैं। इन्ही आरोपो के साथ आक्रोशित परिजन छात्रावास पहुंचकर अपना आक्रोश जताया। तथा जिस कक्ष में करण फंदे पर लटका उस छात्रावास कक्ष का उनके द्वारा ही निरीक्षण करने की बात कही। और अंदेशा किया कि, कहीं किसी हत्यारे ने करण को मौत के घाट उतार कर खिड़की को वेल्डिंग कर भाग गया हो।

तहसीलदार द्वारा सील किए गए कक्ष को खोलने हेतु तहसीलदार से चर्चा की और मौके पर तहसीलदार व पुलिस पहुंची। छात्र करण के परिजनों को देखने व निरीक्षण करने हेतु कक्ष खोला गया। तथा टीआई आरसी भास्करे व तहसीलदार सुनील डावर ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया।

वहीं परिजनों का यह भी आरोप कि, 1 बजे तक छात्रावास के प्रशासन ने करण के कक्ष से बाहर नहीं आने का कारण क्यों नहीं जाना...? जबकि सोमवार को गणित का त्रैमासिक पेपर था। जिसके कारण साथी दोस्त परीक्षा देने हेतु करण को बुलाने जाने हेतु कक्ष में पहुंचे। जिसके बाद अंदर से दरवाजा बंद होने व अंदर से कोई जवाब नहीं मिलने पर अन्य छात्रों के साथ छात्रावास के कर्मचारी हरकत में आए और दरवाजा तोड़ने पर करण फंदे पर लटका मिला।

पुलिस व प्रशासन को चाहिए कि, वह उक्त आत्म हत्या का कारण अवश्य जाने। क्योंकि हमारे देश के यह भविष्य इस तरह से आत्महत्या करते रहेंगे तो यह किसी के लिये भी सही नहीं है।

भाजपा पार्षद पति के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज

विवादः महिला के पति ने आत्महत्या का किया प्रयास, पति के खिलाफ भी मामला दर्ज

माही की गूंज, पेटलावद।

नगर परिषद पेटलावद में कुछ भी सही नही चल रहा है और आए दिन परिषद किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहती है। नगर परिषद में पदस्थ सीएमओ आशा मैड़ा लगातार राजनेतिक चर्चा का विषय बनी हुई है। तो यहां के पार्षद भी किसी न किसी मामले में सुर्खिया बटोर रहे है, खास कर पार्षद पति जिनकी संख्या परिषद में ज्यादा है।

शुरुआत परिषद के अध्यक्ष पति से हुई थीं जिनके ऊपर बलात्कार का मामला दर्ज हुआ था। नए सीएमओ आशा मैड़ा के आने के बाद उपाध्यक्ष पति निशाने पर रहे और उनकी इंट्री पर सीएमओ ने लगाम लगाई और भाजपा मंडल में अध्यक्ष बनने के बाद भी भाजपा की परिषद होने व पत्नी के उपाध्यक्ष होने के बाद भी उनका स्वागत सत्कार स्थानीय परिषद में नही हूआ। वही एक पार्षद के ठेकेदार पति को सीएमओ ने ब्लैक लिस्टेड कर दिया, अभी कुछ दिनों पूर्व ही एक पार्षद पति का नाम जुआ कांड में सामने आया था। अब एक बार फिर वार्ड क्रमांक 5 की महिला पति का नाम सुर्खियों में है, जिन पर एक महिला ने छेड़छाड़ का प्रकरण दर्ज करवाया है।

पार्षद पति पर लगे छेड़छाड़ के आरोप

भाजपा नेताओं द्वारा लगातार महिलाओ से अवैध संबध या शोषण की खबरे मीडिया में अलग-अलग क्षेत्रों से आती रहती है जिसको लेकर भाजपा, विपक्ष के निशाने पर रहती है। एक बार फिर स्थानीय भाजपा में हलचल है। यहां वार्ड क्रमांक 5 के पार्षद पति पर छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगे है और थाना पेटलावद में पार्षद पति के विरुद्ध मामला दर्ज हुआ है। महिला ने खुद अपने आवेदन में पार्षद पति से पूर्व में प्रेम संबध होने की बात स्वीकार की है। महिला द्वारा दर्ज शिकायत के अनुसार 8 सितम्बर को मंदिर पर पूजा करने गई थी इस दौरान मंदिर से बहार आकर पति का इंतजार कर रही थी, जब पार्षद पति ने आकर उससे छेड़छाड़ की ओर चिल्ला चोट करने पर पार्षद पति भाग गया।

पति-पत्नी के बीच हुआ विवाद

हालाकि मामला पुर्व में भी कई बार सुर्खियों में आता रहा है और पूर्व में भी थाने तक पहुंच चुका है। लेकिन आपसी समझौते के माध्यम से मामला आगे नही बड़ा। लेकिन इस बार मामले ने बड़ा तुल पकड़ लिया। बताया जा रहा है इस मामले के बाद महिला और उसके पति के बीच भी विवाद हुआ, महिला ने थाने में पति के विरुद्ध भी शिकायत दर्ज करवाई कि, चरित्र शंका को लेकर मारपीट की जिससे उसे चोट आई। महिला ने पति पर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने की शिकायत दर्ज करवाई है। इस बीच महिला के पति द्वारा जहरीला पदार्थ खाने की बात सामने आई है। जिसको इलाज के लिए सिविल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है।

थाना प्रभारी निर्भयसिह भूरिया ने इस संबध में बताया कि, महिला की रिपोर्ट पर छेड़छाड़ करने के मामले में दीपक निमजा और मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में महिला के पति पर मामला दर्ज हुआ है। वही महिला के पति द्वारा आत्महत्या के प्रयास को लेकर थाना प्रभारी ने बताया कि, फिलहाल जानकारी मिली है लेकिन महिला के पति ने कोई बयान नही दिया है मामले में जाच व कार्यवाही जारी है

फसल बीमा की राशि को लेकर उग्र हुए किसान, रायपुरिया-राजगढ़ मार्ग पर किया चक्काजाम

मुख्यमंत्री से मुलाकात करवाने के आश्वासन पर हटे किसान, जनपद अध्यक्ष ने की मध्यस्ता

माही की गूंज ,बनी/पेटलावद।
ऋषभ गुप्ता

13 अगस्त को किसान पहली बार फसल बीमा की राशि को लेकर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के पास एक ज्ञापन लेकर पहुंचे थे जो की उनकी उपस्थिति में ज्ञापन लेने की बात किसान संगठन से तय हुई थी। वादे के मुताबिक 15 से 20 किसान ज्ञापन में अपनी मांग लेकर पहुंचे लेकिन एसडीएम ज्ञापन लेने नही आई और नाराज किसान वही धरने पर बैठ गए। राजस्व के दूसरे अधिकारियों ने 18 अगस्त की तारीख तय कर किसानो की फसल बीमा राशि पर जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा प्रमाणित जानकारी देने का वादा कर धरना खत्म किया। 18 अगस्त को किसान दोबारा तहसील कार्यालय पहुंचे जहा उनको मिले आश्वासन अनुसार कोई सुनवाई नही हुई तो दोबारा किसान धरने पर बैठ रहे और जब कोई सुनवाई नही हुई तो बीएसएनएल टावर पर चढ़ कर विरोध करने का प्रयास किया। जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन और राजस्व के अधिकारियो ने 15 दिन का समय और मांगा जिसके बाद किसान संगठन ने विरोध प्रदर्शन बंद किया। 15 दिन से अधिक समय बीत जाने के बाद जब प्रशासन की ओर से कोई सुनवाई नहीं हुई तो नाराज किसान मंगलवार को सुबह 9 बजे के लगभग ग्राम बनी में फसल बीमा राशि से वंचित रहने की मांग को लेकर लामबंद होकर किसान ग्राम बनी में मुख्य मार्ग पर आए और बैलगाड़ी लगाकर रास्ते को रोक दिया। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन के आला अफसर पहुंचे। लेकिन किसान अपनी मांग को लेकर तीखे तेवर में ही दिखाई दिए। 12 सितंबर को मुख्यमंत्री पेटलावद आ रहे है जिसको लेकर प्रशासन पहले से अलर्ट मोड़ पर है। जानकारी मिलते ही एसडीओपी अनुरक्ति साबनानी, तहसीलदार अनिल बघेल, नायब तहसीलदार विजेंद्र कटारा, रायपुरिया थाना प्रभारी जीआर बर्डे आंदोलनरत किसानों के बीच पहुंचे तथा उनसे बातचीत शुरू की। लेकिन पिछले दो आंदोलनों की समझाइश में समय निकलने के बाद समस्या हल नहीं होने का हवाला देकर डटे रहे।

जनपद अध्यक्ष ने निभाई महत्वपूर्ण भूमिका

इस दौरान दोनों और बाईक एवं अन्य वाहनों की कतार लग गई। किसान इस दौरान नारेबाजी करते रहें। सूचना मिलने पर जनपद अध्यक्ष रमेश सोलंकी, किसानों के बीच पहुंचे और मध्यस्ता करने में लगे रहे।

प्रदर्शनकारी किसानों ने कहा कि, जनपद अध्यक्ष हमे आश्वत करे कि, 12 सितम्बर को पेटलावद आ रहे सीएम डॉ मोहन यादव से सभा के पूर्व हेलीपेड पर हम किसानों के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात करवाएंगे। आखिर में 3 घंटे के बाद उक्त आश्वासन मिला और चक्काजाम को खत्म करने की सहमति बनी और किसानो ने जाम खत्म किया। फसल बीमा के नाम पर राशि लेने के बाद इस क्षेत्र के किसानों को मुआवजा नहीं मिलने की शिकायत पर बीमा कंपनी से संबंधित अधिकारी कृषि विभाग के अमले के साथ आए। किसानों के साथ उन्होंने जमीन पर बैठकर चर्चा भी की लेकिन वो भी संतुष्ट नहीं कर पाए। किसानों ने सर्वे से वंचित इलाकों में पुनः सर्वे करवाने की बात कही, तो अधिकारी बोले कि इस साल से सर्वे सेटेलाइट के जरिए हुआ है। जिससे भेदभाव के आरोप निराधार है। लेकिन साथ में उन्होंने टोल फ्री नंबर देते हुए कहा कि, जलभराव के कारण किसी की फसल बर्बाद हुई हो तो इस पर शिकायत कर सकते है।

बीमा कंपनियों को फायदा दिला रहे

आंदोलनकारी किसानों ने एक स्वर में कहा कि, हर साल फसल बीमा के नाम पर उनके खातों से हजारों रुपए काट लिए जाते हैं और बीमा कंपनियों को करोड़ों रुपए का लाभ पहुँचाया जाता है। इसके बावजूद जब प्राकृतिक आपदाओं या मौसम की मार से फसलें बर्बाद होती हैं, तब किसानों को उचित बीमा राशि नहीं मिलती। इस दौरान किसान अपने हाथों में खराब फसलों को भी लहराते रहे।

तहसीलदार को दिया ज्ञापन

जनपद अध्यक्ष सोलंकी के आश्वासन के बाद किसानों ने तहसीलदार अनिल बघेल को ज्ञापन सौंपा। वाचन करते हुए भारतीय किसान यूनियन के महामंत्री जितेंद्र पाटीदार ने कहा कि, जब तक हमें अपना हक नहीं मिलता हमारा संघर्ष जारी रहेगा।

भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष महेंद्र हामड़ ने कहा कि, अभी तो हमने जनपद अध्यक्ष सोलंकी की बात पर आंदोलन स्थगित किया है, लेकिन यदि प्रशासन हमारी मांगों पर विचार नहीं करेगा तो आगे फिर उग्र आंदोलन होगा।

रमेश सोलंकी, जनपद अध्यक्ष ने कहा कि, प्रदेश के मुखिया डॉ मोहन यादव किसानों के हित चिंतक हैं। आज के आंदोलन की जानकारी कैबिनेट मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया को भी दी थी। उनसे चर्चा कर किसानों के प्रतिनिधिमंडल को सीएम से मिलवाया जाएगा इसका पूरा आश्वासन मिला है।

संपादकीय

नेपाल बेहाल

नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन लगाने के बाद उग्र हुआ आंदोलन आखिरकार संवैधानिक संकट में बदल गया और सरकार गिरने का कारण बना। यहां तक कि मंत्रियों के बाद प्रधानमंत्री के.पी. ओली तक को इस्तीफा देने को मजबूर होना पड़ा। उग्र युवाओं ने संसद, सुप्रीम कोर्ट, मंत्रियों के आवास व कुछ मीडिया हाउस को भी निशाना बनाया। भले ही तात्कालिक रूप से सोशल मीडिया पर बैन को हिंसा की वजह बताया जा रहा हो, लेकिन यह प्रतिक्रिया तात्कालिक नहीं थी। युवाओं की दशकों की हताशा और राजनीतिक कदाचार, काहिली व निरंकुशता के चलते गुस्सा नेपाल की सड़कों पर लावा बनकर फूटा है। नेपाल सरकार की सख्ती से आंदोलनकारियों के दमन ने आग में घी का काम किया। नेपाल की राजनीति में अवसरवाद व राजनीतिक अस्थिरता ने भी सरकारों के प्रति युवाओं के आक्रोश को बढ़ाया है। विडंबना देखिए कि 17 बरसों में यहां 14 सरकारें बन चुकी हैं। बहरहाल इस हिंसक प्रतिकार में 19 से अधिक युवाओं को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। दरअसल, शुरुआत में सोशल मीडिया साइटों पर एक विवादास्पद प्रतिबंध ने युवा नेतृत्व वाले जेन-जेड समूह के गुस्से को भड़का दिया। यह समूह सत्ता के शीर्ष पदों पर कथित भ्रष्टाचार और उनकी संतानों के विलासी जीवन के खिलाफ अभियान चला रहा था। इस युवा ब्रिगेड ने लोकप्रिय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके दावा किया कि मंत्रियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की संतानों की फिजूलखर्ची भरी जीवनशैली अवैध धन-दौलत की बदौलत है। इस पोल-खोल अभियान से घबरायी सरकार ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने का असफल प्रयास किया। सरकार का यह दांव उस पर ही उलटा पड़ा और सरकार की ही विदाई हो गई। हालांकि, युवाओं का आक्रोश देखते हुए सरकार ने प्रतिबंध हटाने की घोषणा की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वैसे इस आंदोलन के दौरान जिस तरह हिंसा, आगजनी व तोड़फोड़ हुई, वह दुर्भाग्यपूर्ण ही कही जाएगी। युवाओं की हिंसक भीड़ ने मंगलवार को संसद, सर्वोच्च न्यायालय, राजनीतिक दलों के कार्यालयों और मंत्रियों के घरों को निशाना बनाया।

दरअसल, आंदोलनकारी शासन व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन और भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते रहे हैं। उनकी मांग रही कि सोमवार को पुलिस गोलाबारी में हुई मौतों के लिये जिम्मेदार लोगों को कड़ी सजा दी जाए। अराजकता और अव्यवस्था के बीच, काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी के मेयर, बालेन शाह, एक प्रभावशाली हितधारक के रूप में उभरे हैं। इस पैंतीस वर्षीय पूर्व रैपर ने भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया प्रतिबंध के खिलाफ आंदोलन का समर्थन करके जेन-जेड का विश्वास जीता है। उन्होंने संसद भंग करने की मांग की है। जिसके बाद सैन्य अधिकारियों और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत हुई। निस्संदेह, मौजूदा वक्त में सेना की बड़ी भूमिका होने के बाद अब उसके व सुरक्षा एजेंसियों के लिये तात्कालिक चुनौती अस्थिर स्थिति पर नियंत्रण और सामान्य स्थिति को बहाल करने की होगी। आने वाले दिनों में व्यवस्थागत सुधारों के रोडमैप पर चर्चा के साथ बातचीत के जरिये संकट का समाधान करना प्राथमिकता होनी चाहिए। दरअसल, ओली और उनके पूर्ववर्तियों की नीतियों की विफलता ने युवाओं में निराशा व मोहभंग को बढ़ावा दिया है। वहीं इस उथल-पुथल के मूल में नेपाली अर्थव्यवस्था का संकट भी है, जो पर्यटन और प्रवासी नागरिकों द्वारा भेजी जाने वाली रकम पर निर्भर रही है। विडंबना यह है कि इन दोनों स्रोतों में पिछले वर्षों में कमी आई है। बेरोजगारी दर का बीस फीसदी के आसपास होना युवाओं के आक्रोश को तार्किक बनाता है। दरअसल, सरकार युवाओं की उम्मीदों की कसौटी पर खरा उतरने में नाकाम ही रही है। आये दिन नेताओं द्वारा किए जाने वाले वायदों से खिन्न युवा धरातल पर बदलाव देखना चाहते हैं। बहरहाल, मौजूदा उथल-पुथल ने नेपाल को एक नई शुरुआत करने का अवसर जरूर दिया है। वहीं भारत के लिये भी यह सचेतक घटनाक्रम है कि उसके पड़ोस में श्रीलंका, बांग्लादेश के बाद नेपाल में जनाक्रोश में विदेशी जमीन से संचालित सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका रही है। युवाओं की आकांक्षाओं और रोजगार की चुनौती को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। निस्संदेह, सोशल मीडिया ने युवाओं की आकांक्षाओं को सातवें आसमान पर पहुंचाया है और हकीकत में हमारा धरातल खासा खुरदरा है।

अब हिमालय बसाओ अभियान की जरूरत

साठ के दशक में भारत में पहली बार 'हिमालय बचाओ' का नारा चर्चा में आया था। उस समय तक तिब्बत में चीन जम गया था। भारत-चीन युद्ध हो चुका था। स्वाभाविक था कि उस समय के हिमालय बचाओ अभियान के उद्देश्य प्रमुखतया सामरिक व सांस्कृतिक थे। इसमें पड़ोसी हिमालयी देशों में आपसी विश्वास व मेलजोल बनाना भी शामिल था। डॉ?. राममनोहर लोहिया इस विचार के प्रवर्तकों में से एक थे। तिब्बत से एकजुटता को भी इससे जोड़ा गया।

सत्तर के दशक में वैश्विक मंचों में पर्यावरण की बातें मुख्य मुद्दा बनने लगी थीं। 1970 व 80 के दशक में हिमालय में भी व्यावसायिक वन कटान तथा अंधाधुंध खनन से मानव व प्रकृति को होने वाले नुकसान के खिलाफ जन आन्दोलन प्रारंभ हुए। चमोली में सफल चिपको आन्दोलन हुआ। मसूरी, देहरादून, टिहरी गढ़वाल में चूना खदानों से हिमालय व हिमालय वासियों को नुकसान के मद्देनजर खनिज खदानें बन्द करवाने को लेकर आन्दोलन हुए।

पर्यावरणीय चेतना और टिहरी बांध विरोधी आन्दोलन के दौरान सुन्दरलाल बहुगुणा के आह्वान पर मई, 1992 में पुनः नये संदर्भों में 'हिमालय बचाओ' अभियान को जन्म दिया गया। इसके तहत टिहरी बांध जलाशय में समाहित पुरानी टिहरी के भागीरथी तट पर हिमालय से जुड़े सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक व वैज्ञानिक कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ। इस अभियान ने मुख्यतया हिमालयी वनों की तबाही रोकने की अपील की गई।

आमजन को भी अनुभव होने लगा कि वन उपज और खनिज के लिए खोखला होता हिमालय अब उसके कुदरती जल संसाधनों के व्यावसायिक दोहन के कारण भी आघात ग्रस्त हो रहा है। उसके पारम्परिक जलस्रोत और नदियां सूख रही हैं। उसकी नदियों को कहीं मोड़ा जा रहा है, कहीं सुरंगों में डाला जा रहा है तो कहीं सुखाया जा रहा है। इक्कीसवीं सदी में हिमालय बचाओ अभियान में नदियों और नदी घाटियों को बचाने के मुद्दे प्रमुख बन गये हैं। बीते दशकों में हिमालयी नदियों पर बने जलाशयी बांधों के कुप्रभावों का अनुभव विस्थापन व नदियों की उपजाऊ घाटियों को डुबाये जाने के परिणामों से होने लगा है। वर्ष 2012 की हिमालय लोक नीति के तैयार प्रारूप में कहा गया था कि अधिकतर हिमालयी राज्यों की सरकारों ने नदियों को रोककर विद्युत ऊर्जा बनाने के लिए सैकड़ों हाइड्रो प्रोजेक्ट निर्माण का बीड़ा उठा लिया है। लेकिन इन जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण से पहले जन जीवन पर असर व इनसे सम्पूर्ण हिमालयी जन-जीवन खतरे में पड़ता नजर नहीं आ रहा है। इन परियोजनाओं से आजीविका के प्राकृतिक संसाधनों का अतिक्रमण भी हो रहा है। इस समय हिमालयी क्षेत्रों में प्रस्तावित, निर्माणाधीन व निर्मित करीब 1000 हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं। इनके कारण लोगों का बड़ी संख्या में विस्थापन चिंता की बात है। हिमालयी नीति, जिसे बनाने के लिए बार-बार केन्द्र पर दबाव डाला जाता रहा है, केवल हिमालय बचाओ नीति तक ही सीमित नहीं हो सकती है। इसमें हिमालय बसाओ नीति की रणनीति का भी समावेश करना होगा। क्योंकि कई

क्षेत्र सामरिक महत्व के भी हैं। हालांकि आये दिन जलवायु बदलाव व मानवीय लालच से आपदा झेलते भारतीय हिमालय में बसाओ का काम भी आसान नहीं। सूची में रोज ऐसे गांव-कस्बे जुड़ रहे हैं जो भूधंसाव व भूस्खलनों के कारण वहां के बाशिन्दों के लिए असुरक्षित हो गये हैं। विकास व पर्यावरण संरक्षण को लेकर स्थानीय समुदाय की आकांक्षाओं व आशंकाओं दोनों को नजरअन्दाज किया जा रहा है। यह मानव अधिकारों का भी मुद्दा है। निस्संदेह पहाड़ों के विकास और पहाड़ी जन के विकास में द्वंद्व को मिटाना होगा। यदि हिमालय के पहाड़ी गांवों को बचाना व बसाना है तो खेती को लाभकारी बनाना ही होगा। पहाड़ की खेती के लिए टेक्नोलॉजी व संसाधन पर खर्च बढ़ाना होगा। टेक्नोलॉजी व कृषि प्रसार के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि पहाड़ों में प्राथमिक किसान वहां की महिलाएं ही होती हैं। बड़े पैमाने पर जलागम प्रबंधन करना होगा। खेती के लिए जंगलों से स्थानीय जन को लघु वन उत्पादों को जरूरत भर लेने की छूट देनी होगी। पहाड़ी खेती में, सततता बनाये रखने को पचास प्रतिशत से ज्यादा वन संसाधनों का पारम्परिक उपयोग होता है।

पहाड़ों को बसाने के क्रम में पहाड़ी कस्बों को बसाने की स्थानीय परिवेश के अनुरूप विशेष नीति, टेक्नोलॉजी, विज्ञान व मल मूत्र कचरा निस्तारण का ज्ञान अर्जित करना होगा, व उसे अमल में भी लाना होगा। बाजारों व आपदा लाने की आशंका से रहित पहाड़ी सड़कें कैसे बनायी जा सकेंगी, इसकी हिमालयी विकास नीति में ठोस राह तय करनी होगी। पहाड़ों पर जो भार न बनें, ऐसे उद्योग तलाशने होंगे। मौसमी भविष्यवाणी तंत्र को स्थानीय पहुंच के अनुरूप भरोसमंद बनाना होगा। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में अलग-थलग पड़े होने के अहसास को कम करने के लिए किफायती मोबाइल टेलीफोन सुविधा का प्रसार भी आवश्यक है।

वीरेन्द्र कुमार

संवेदनशील हिमालय आपदाओं का घर भी है। भूस्खलन, बादल विस्फोट, दावानल, बाढ़ जैसी बारम्बार आने वाली आपदाएं हैं। भूकम्प भी आते रहे हैं। जलवायु बदलाव हिमालय के तापक्रम को तेजी से बढ़ा रहा है। इससे आर्थिक, खाद्य व आवासीय सुरक्षा पर असर पड़ रहा है। इसके लिए हिमालय से बाहर रहने वालों की जरूरतें पूरी करने को हिमालय के अंगभंग की नीति ज्यादा जिम्मेदार हैं। आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में कई बार पूरे के पूरे गांवों को अन्यत्र पुनर्वासित करना आवश्यक हो जाता है। अकेले उत्तराखंड में ही 2000 में अलग राज्य बनने के बाद 400 से ज्यादा गांवों को पुनर्वास के लिए चिन्हित किया गया। इस संदर्भ में भी हिमालय बसाओ के तहत हिमालय के आपदाग्रस्त क्षेत्रों व व्यक्तियों के लिए एक अलग पुनर्वास व आपदा क्षति आकलन नीति होनी चाहिये। यह भी हिमालय नीति का अंग हो।

विडम्बना है, पहाड़-सी समस्याओं के बीच मूल पहाड़ी सरकारी कर्मचारी भी पहाड़ों में सेवा देने के लिए तैयार नहीं होता है। इसीलिए स्कूल बिना शिक्षक, अस्पताल बिना डाक्टर के हो जाते हैं। परिणामस्वरूप पहाड़ वालों के लिए सुशासन पाना भी दिन-ब-दिन मुश्किल होता जा रहा है।

कर सुधार : आर्थिक नीति से सामाजिक न्याय

भारत की राजनीति और अर्थनीति में कर सुधार हमेशा से एक संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण मुद्दा रहा है। लंबे समय तक जटिल कर ढांचे ने नागरिकों और कारोबारियों को उलझाए रखा। वैट, उत्पाद शुल्क और अनेक स्थानीय कर न केवल भ्रम पैदा करते थे बल्कि व्यापार की गति को भी बाधित करते थे। इस पृष्ठभूमि में 2017 में जीएसटी लागू हुआ, जिसने कर प्रणाली को एक राष्ट्रएक करएक बाजार की दिशा दी। किंतु उसकी संरचना जटिल थी और बहु-स्लैब दरों ने कई बार विवाद और असुविधा उत्पन्न की। इसीलिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक ने ÷नेक्स्टजेन जीएसटी सुधारों÷ की घोषणा की, तो यह केवल तकनीकी निर्णय नहीं बल्कि एक वैचारिक बदलाव भी था।

इन सुधारों की सबसे बड़ी विशेषता है कि वे सीधे नागरिकों के जीवन को केंद्र में रखकर बनाए गए हैं। आवश्यक वस्तुओं को करमुक्त करना या न्यूनतम दर पर लाना केवल कर नीति नहीं बल्कि सामाजिक न्याय की दिशा में कदम है। दूध, दही, चावल, आटा और दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर कर छूट गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देती है। यह वही वर्ग है जो महंगाई की सबसे अधिक मार झेलता है और जिस पर पूर्ववर्ती सरकारों ने अक्सर अप्रत्यक्ष करों का बोझ डाला। यूपीए के दौर में जहाँ आटा, चावल और चाय जैसी आवश्यक वस्तुएँ भी कर के दायरे में थीं, वहीं आज मोदी सरकार ने उन्हें छूट देकर साफ कर दिया कि उसकी प्राथमिकता आम नागरिक का बोझ कम करना है। स्वास्थ्य क्षेत्र में उठाया गया कदम भी इसी दृष्टिकोण को दर्शाता है। जीवन और स्वास्थ्य बीमा को करमुक्त करना और जीवनरक्षक दवाओं पर जीएसटी शून्य करना यह दिखाता है कि सरकार केवल

अर्थव्यवस्था के आँकड़ों से नहीं बल्कि लोगों के दुःख-दर्द से भी जुड़ी हुई है। पूर्ववर्ती सरकारें स्वास्थ्य को निजी हाथों में छोड़ कर कर्तव्य पूरा समझ लेती थीं, वहीं मोदी सरकार ने स्वास्थ्य सेवा को नागरिक अधिकार की तरह देखा है।

कृषि सुधारों में भी यही सोच परिलक्षित होती है। किसान केवल वोट बैंक नहीं बल्कि राष्ट्र की रीढ़ हैं, यह दृष्टि भाजपा सरकार ने बार-बार अपने निर्णयों में साबित की है। ट्रैक्टर, सिंचाई उपकरण, खाद और कीटनाशकों पर कर दर कम करना केवल लागत घटाने का उपाय नहीं, बल्कि ग्रामीण समृद्धि और आत्मनिर्भरता का सूत्र है। पिछली सरकारें कृषि क्षेत्र को सब्सिडी तक सीमित रखती थीं, जबकि मोदी सरकार कर ढांचे में ही संरचनात्मक सुधार कर किसानों को स्थायी लाभ पहुंचा रही है। अवसंरचना और उद्योग जगत को भी यह सुधार नए अवसर देता है। सीमेंट पर कर दर घटाना घर बनाने वाले आम नागरिक से लेकर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तक सबके लिए राहत है। छोटे और मझोले उद्योगों (एमएसएमई) को सरल अनुपालन और तेज़ रिफंड प्रक्रिया उपलब्ध कराना वास्तव में उन्हें अर्थव्यवस्था का सशक्त स्तंभ मानने की नीति है। यहाँ तुलना आवश्यक हैकृपिछली सरकारें इस क्षेत्र को नियामकीय बोझ में दबाए रखती थीं, जबकि मोदी सरकार तकनीक जैसे एआई आधारित निगरानी का उपयोग कर पारदर्शिता और सुगमता दोनों ला रही है।

कपड़ा और उर्वरक उद्योग, जो लंबे समय से उल्टे कर ढांचे की मार झेल रहे थे, अब जीएसटी युक्तिकरण से राहत पाएंगे। यह न केवल उद्योग के लिए प्रोत्साहन है बल्कि लाखों कामगारों के लिए भी स्थिरता और रोजगार का आधार है। यहाँ एक और बड़ा फर्क स्पष्ट होता है। पिछली सरकारें सुधारों को अक्सर राजनीतिक गणित और वोट-बैंक से जोड़कर देखती थीं।

अजीत लाड़

नतीजा यह हुआ कि निर्णय या तो टलते रहे या आधे-अधूरे लागू हुए। मोदी सरकार ने दिखाया कि सुधार केवल नारे नहीं होते, वे ठोस नीतिगत हस्तक्षेप होते हैं। यह नेतृत्व की स्पष्टता और दूरदृष्टि है कि दुनिया मंदी की आहट से जूझ रही है और भारत में कर सुधारों को अवसर की तरह लिया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सुधारों से राष्ट्रनिर्माण का वह दृष्टिकोण झलकता है जिसमें अर्थव्यवस्था केवल जीडीपी वृद्धि तक सीमित नहीं बल्कि नागरिकों के जीवन स्तर, उद्योगों की प्रतिस्पर्धा और किसानों की समृद्धि से जुड़ी हुई है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लिए गए ये निर्णय दिखाते हैं कि सरकार की प्राथमिकता ÷सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास÷ को व्यवहार में उतारना है।इसलिए कहा जा सकता है कि नेक्स्टजेन जीएसटी सुधार पूर्ववर्ती सरकारों से अलग एक नई शैली का परिचायक हैं। यह शैली केवल वादों और घोषणाओं की नहीं, बल्कि परिणामों की है। यहाँ नीति और नियत दोनों ही स्पष्ट हैं। सरकार मानती है कि कर ढांचा नागरिकों के जीवन को आसान बनाने का साधन होना चाहिए, न कि बोझ। यही सोच भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में ले जाएगी।

सदैव स्मरणीय रहेगा स्वामी विवेकानंद का शिकागो में दिया भाषण

युवाओं के प्रेरणास्रोत तथा आदर्श व्यक्तिव के धनी माने जाते रहे स्वामी विवेकानंद को उनके ओजस्वी विचारों और आदर्शों के कारण ही जाना जाता है। सही मायनों में वे आधुनिक मानव के आदर्श प्रतिनिधि थे। विशेषकर भारतीय युवाओं के लिए तो भारतीय नवजागरण का अग्रदूत उनसे बढ़कर अन्य कोई नेता नहीं हो सकता। कोलकाता में 12 जनवरी 1863 को जन्मे स्वामी विवेकानंद अपने 39 वर्ष के छोटे से जीवनकाल में समूचे विश्व को अपने अलौकिक विचारों की ऐसी बेशकीमती पूंजी सौंप गए, जो आने वाली अनेक शताब्दियों तक समस्त मानव जाति का मार्गदर्शन करती रहेगी। वे एक ऐसे महान व्यक्तित्व थे, जिनकी ओजस्वी वाणी सदैव युवाओं के लिये प्रेरणास्रोत बनी रही। उन्होंने देश को सुदृढ़ बनाने और विकास पथ पर अग्रसर करने के लिए सदैव युवा शक्ति पर भरोसा किया। दरअसल युवा वर्ग से उन्हें बहुत उम्मीदें थी।

स्वामी विवेकानंद ने 11 सितम्बर 1893 को शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में हिन्दू धर्म पर अपने प्रेरणात्मक भाषण की शुरूआत 'मेरे अमेरिकी भाईयों और बहनों' के साथ की तो बहुत देर तक तालियों की गड़गड़ाहट होती रही। अपने उस भाषण के जरिये उन्होंने दुनियाभर में भारतीय अध्यात्म का डंका बजाया। विदेशी मीडिया और वक्ताओं द्वारा भी स्वामीजी को धर्म संसद में सबसे महान व्यक्तित्व और ईश्वरीय शक्ति प्राप्त सबसे लोकप्रिय वक्ता बताया जाता रहा। स्वामी विवेकानंद की चर्चा जब भी होती है तो अमेरिका के शिकागो की धर्म संसद में वर्ष 1893 में दिए गए उनके उस ओजस्वी भाषण की चर्चा अवश्य होती है। उसी ओजस्वी भाषण को यादगार बनाए रखने और युवाओं को उस भाषण के जरिये ऊर्जावान बनाए रखने के लिए ही प्रतिवर्ष 11 सितम्बर का दिन 'शिकागो वक्तृता दिवस' के रूप में मनाया जाता है। यह स्वामी विवेकानंद का अद्भुत व्यक्तित्व ही था कि वे यदि मंच से गुजरते भी थे तो तालियों की गड़गड़ाहट होने लगती थी। युवाओं की अहम् भावना को खत्म करने के उद्देश्य से ही स्वामी विवेकानंद ने अपने एक भाषण में कहा था कि यदि तुम स्वयं ही नेता के रूप में खड़े हो जाओगे तो तुम्हें सहायता देने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए यदि सफल होना चाहते हो तो सबसे पहले अपने अहम् का नाश कर डालो। उनका कहना था कि मेरी भविष्य की आशाएं युवाओं के चरित्र, बुद्धिमत्ता, दूसरों की सेवा के लिए सभी का त्याग और आज्ञाकारिता, खुद को और बड़े पैमाने पर देश के लिए अच्छा करने वालों पर निर्भर है।

युवा शक्ति का आव्हान करते हुए स्वामी विवेकानंद ने अनेक मूलमंत्र दिए, जो देश के युवाओं के लिए सदैव प्रेरणास्रोत बने रहेंगे। उनका कहना था, ''ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारी हैं। वो हम ही हैं, जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। मेरा विश्वास युवा पीढ़ी में है, आधुनिक पीढ़ी से मेरे कार्यकर्ता आ जाएंगे। डर से भागो मत, डर का सामना करो। यह जीवन अल्पकालीन है, संसार की विलासिता क्षणिक है लेकिन जो दूसरों के लिए जीते हैं, वे वास्तव में जीते हैं। जो भी कार्य करो, वह पूरी मेहनत के साथ करो। दिन में एक बार खुद से बात अवश्य करो, नहीं तो आप संसार के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति से मिलने से चूक जाओगे। उच्चतम आदर्श को चुनो और उस तक अपना जीवन जीयो। सागर की तरफ देखो, न कि लहरों की तरफ। महसूस करो कि तुम महान हो और तुम महान बन जाओगे। काम, काम, काम, बस यही आपके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। धन पाने के लिए कड़ा संघर्ष करो पर उससे लगाव मत करो। जो गरीबों में, कमजोरों में और बीमारियों में शिव को देखता है, वो सच में शिव की पूजा करता है। पृथ्वी का आनंद नायकों द्वारा लिया जाता है, यह अमोघ सत्य है, अतः एक नायक बनो और सदैव कहो कि मुझे कोई डर नहीं है। मृत्यु तो निश्चित है, एक अच्छे काम के लिए मरना सबसे बेहतर है। कुछ सच्चे, ईमानदार और ऊर्जावान पुरुष तथा महिलाएं एक वर्ष में एक सदी की भीड़ से अधिक कार्य कर सकते हैं। विश्व एक व्यायामशाला है, जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं।''

युवा शक्ति का आव्हान करते हुए स्वामी जी ने एक मंत्र दिया था, 'उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत' अर्थात् 'उठो, जागो और तब तक मत रूको, जब तक कि मंजिल प्राप्त न हो जाए।' ऐसा अनमोल मूलमंत्र देने वाले स्वामी विवेकानंद ने सदैव अपने क्रांतिकारी और तेजस्वी विचारों से युवा पीढ़ी को ऊर्जावान बनाने, उसमें नई शक्ति एवं चेतना जागृत करने और सकारात्कमता का संचार करने का कार्य किया। उनका कहना था कि अधिकांश लोग तो भेड़ों के झुंड के समान हैं। यदि आगे की एक भेड़ गड्ढे में गिरती है तो पीछे की सभी भेड़ें भी उसमें गिरती जाती हैं। इसी प्रकार समाज का मुखिया भी जब कोई बात कहता है तो दूसरे लोग भी उसका अनुकरण करने लगते हैं लेकिन यह नहीं सोचते कि वे कर क्या रहे है। जब मनुष्य को ये सांसारिक बातें निस्सार प्रतीत होने लगती हैं, तब वह सोचता है कि वह अपनी वृत्ति के हाथों का खिलौना बन चुका है और उस समय वह चाहता है कि खिलौना बनकर वह उसके बहकावे में न आए क्योंकि यह तो गुलामी है। स्वामी जी ने 1 मई 1897 को कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन तथा 9 दिसम्बर 1898 को कलकत्ता के निकट गंगा नदी के किनारे बेलूर में रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी। इसी रामकृष्ण मठ में 4 जुलाई 1902 को ध्यानमग्न अवस्था में महासमाधि धारण किए वे चिरनिद्रा में लीन हो गए।

योगेश कुमार गोयल

नर्सिंग कॉलेज का धोखा, विद्यार्थी से फीस लेकर नहीं करवाई परीक्षा

माही की गूंज, मंदसौर।

अनियमितता और फर्जीवाड़े को लेकर चर्चा में बने रहने वाले मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, उपभोक्ता फोरम ने मंदसौर के एक नर्सिंग कॉलेज को विद्यार्थी की ब्याज सहित पूरी फ़ीस वापस करने और उसे शैक्षणिक हर्जाने के रूप में 1 लाख रुपये ब्याज सहित देने के निर्देश दिए हैं।

मध्य प्रदेश की नर्सिंग शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाने वाला एक बड़ा मामला मंदसौर से सामने आया है। यहां श्री जी नर्सिंग कॉलेज ने एडमिशन लेने वाली एक छात्रा से फीस तो ली लेकिन न परीक्षा कराई और न ही सही रसीद दी। शिकायत करने पर जब एडमिशन रद्द कर पैसे और दस्तावेज लौटाने की मांग की गई तो कॉलेज ने साफ़ इंकार कर दिया।

कॉलेज प्रबंधन ने नहीं सुनी, छात्रा ने खटखटाया कानून का दरवाजा

दरअसल 2022 में बी.एससी नर्सिंग में दाखिला लेने वाली रेणुका डांगी ने दो साल इंतज़ार किया, मगर

परीक्षा का कोई अता-पता नहीं चला। अंततः छात्रा ने चुप्पी तोड़ते हुए क़ानून का सहारा लिया। उसने उपभोक्ता फोरम में शिकायत की, मामले की सुनवाई करते हुए मंदसौर जिला उपभोक्ता प्रतितोषण आयोग ने कॉलेज के रवैये को शिक्षा के अधिकार और छात्रा के भविष्य के साथ खिलवाड़ माना।

आयोग ने कॉलेज को दिए ये आदेश

1,00,500/- रुपये फीस वापस करे।
1 लाख रुपये शैक्षणिक हर्जाने के तौर पर दे।
10,000 रुपये मानसिक प्रताड़ना के लिए अदा करे।
इन सभी राशि पर 6 वार्षिक ब्याज लगाया जाए।
30 दिन में छात्रा की टीसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट उपलब्ध कराए।

कई कॉलेजों में चल रहा गोलमाल

उल्लेखनीय है कि यह मामला अब केवल रेणुका डांगी या मंदसौर के किसी एक कॉलेज तक सीमित नहीं रहा।

नीमच समेत प्रदेश के कई नर्सिंग कॉलेजों में छात्रों को इसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है कि क्लास नहीं, परीक्षा नहीं, जवाबदेही नहीं।

क्या कहना है विशेषज्ञों का

रेणुका की लड़ाई और आयोग का यह आदेश छात्रों में नई उम्मीद जगाता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले दिनों में ऐसे मामलों की संख्या और बढ़ सकती है और नर्सिंग शिक्षा के नाम पर चल रहे कारोबार पर सख्त कार्रवाई का रास्ता खुल सकता है।

नर्सिंग होम में कोबरा दिखने से मचा हड़कंप

माही की गूंज, शाजापुर।

शहर में बस स्टैंड पर स्थित एक नर्सिंग होम में कोबरा सांप घुसने से हड़कंप मच गया। जैसे ही अस्पताल के स्टाफ और मरीजों ने जहरीले कोबरा को देखा तो उनके पसीने छूट गए। तुरंत स्नेक कैचर को हॉस्पिटल में सांप निकलने की सूचना दी गई जिसके बाद स्नेक कैचर मौके पर पहुंचा और करीब पौन घंटे की मशक्कत के बाद सांप का रेस्क्यू कर अपने साथ ले गया।

नर्सिंग होम में कोबरा

शाजापुर में बस स्टैंड स्थित पाटीदार नर्सिंग होम में दोपहर को करीब 1 बजे एक ब्लैक कोबरा दिखाई दिया। ये सांप अस्पताल के ड्रेसिंग रूम में था। अस्पताल प्रबंधन ने सांप को पकड़ने के लिए स्नैक केचर एक्सपर्ट जितेंद्र मालवीय को सूचना दी। मौके पर पहुंचे मालवीय ने सावधानी से सांप का रेस्क्यू प्रारंभ किया। कुछ देर की मशक्कत के बाद उन्होंने मालवीय ने कोबरा को पकड़ लिया।

सांप पकड़े जाने के बाद ली राहत की सांस

कोबरा सांप का रेस्क्यू करने के बाद स्नेक कैचर जितेन्द्र मालवीय ने बताया कि सांप 4 से 5 फीट लंबा था। जिसे डिब्बे में बंद कर वो अपने साथ जंगल ले जा रहे हैं जहां उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ देंगे। सांप के पकड़े जाने के बाद अस्पताल प्रबंधन और मरीजों ने राहत की सांस ली। नर्सिंग होम के संचालक डॉ. राजकुमार पाटीदार ने बताया कि सांप कहां से आया इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन तत्काल रेस्क्यू एक्सपर्ट को बुलवाकर इसे सुरक्षित जंगल में छुड़वा दिया गया है।

पेड़ से टकराई बच्चों से भरी स्कूल बस

माही की गूंज, मंदसौर।

जिले में स्कूल बस पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में सात बच्चे घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए गरोठ चिकित्सालय ले जाया गया। हादसे में एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे हायर सेंटर रेफर किया गया है।

गरोठ थाना क्षेत्र के कुंडालिया के पास एक तेज रफ्तार स्कूल बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। बताया जा रहा है कि हादसे के समय लगभग 12 से बच्चे स्कूल बस में सवार थे, जिनमें से 7 बच्चों को चोट आईं इन्हें इलाज के लिए गरोठ चिकित्सालय लाया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

बाह्मणों के वास में हुई चोरी का सात दिनों में पर्दाफाश

माही की गूंज, रतलाम।

शहर के ब्राम्हणो के वास में स्थित एक घर में हुई चोरी का सात दिनों के भीतर पर्दाफाश कर दिया है। चोरी की वारदात में शामिल तीन आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए चोरी के गहने और नगदी को भी बरामद कर लिया गया है। पकडे गए आरोपियों में से दो आरोपी नाबालिग बच्चे है।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक विगत 2 सितम्बर को धान मंडी रतलाम के निवासी विशाल पिता रमेशचन्द्र व्यास 42 वर्ष निवासी- 62 दयानंद मार्ग धानमण्डी रतलाम ने थाना माणक चौक रतलाम पर घर मे चोरी के संबंध मे रिपोर्ट दर्ज कराइ थी। इस मामले में माणकचौक रतलाम पर अप.क्र. 472/2025, धारा 331(3), 305 बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना मे लिया गया। विवेचना मे आरोपीयो की गिरफ्तारी के लिये एक विशेष टीम बनायी गई।

पुलिस की विशेष टीम ने त्वरीत कार्यवाही करते रतलाम शहर के सम्भावित रास्तो के सीसीटीवी फुटेज व मुखबीर सूचना के आधार पर संदीग्ध दो - तीन लडके की तलाश की। इसी दौरान विश्वनीय मुखबीर सूचना प्राप्त हुई कि विधिविरुध्द बालक 02 व अशोक पिता रमेश मईडा निवासी हरीजन बस्ती सिलावटो का वास रतलाम ने मिलकर धानमंडी मे एक मकान मे चोरी की है। विधिविरुध्द बालक व आरोपी को घेराबंदी करके पकड़ा गया।

पुछताछ करने पर विधिविरुध्द बालक व आरोपी द्वारा घटना दिनाँक को चोरी करना कबुल कर लिया और पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई सोने का मंगलसूत्र , एक जोडी सोने की पाटली , एक जोडी कान की सोने की झुमकी , सोने की एक अंगुठी , माथे का टीका सोने के आभुषणो एवं नगदी रुपये 5000/- बरामद कर लिए। चोरी में लिप्त विधिविरुध्द बालक को बाल संपेक्षण गृह भेजा गया है तथा आरोपी अशोक पिता रमेश मईडा निवासी हरीजन बस्ती सिलावटो का वास रतलाम से प्रकरण सदर मे व चोरी के अन्य प्रकरणो मे भी पुछताछ की जा रही है।

हिंदू नाम रखकर मुस्लिम युवक ने किया दुष्कर्म

माही की गूंज, रतलाम। थाना औद्योगिक क्षेत्र अंतर्गत मुस्लिम युवक द्वारा नाम बदलकर हिंदू युवती से दोस्ती कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने युवती की रिपोर्ट पर आरोपित युवक शिवनगर निवासी वसीम पुत्र युसूफ खान व उसकी बहन रोशनी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।

पुलिस के अनुसार, युवती ने रिपोर्ट में बताया कि अक्टूबर 2024 में नानी के घर रतलाम आने के दौरान उसकी पहचान किराने की दुकान पर वसीम से हुई। वसीम ने इस दौरान अपना नाम विक्कीसिंह बताया। बातचीत में मोबाइल नंबर भी ले लिए और काल करने लगा। 23 मार्च 2025 को उसने काल कर रतलाम बुलाया और एक गोदाम पर ले जाकर दुष्कर्म किया, जिससे वह गर्भवती हो गई। इसकी जानकारी मिलने पर वसीम के घर पहुंची तो वहां उसकी बहन रोशनी मिली। बहन ने बताया कि हम मुस्लिम हैं। यह बात किसी को बताना मत। बाजार से गर्भपात की गोली लाकर दे दूंगी। दवा देकर गर्भपात भी करा दिया। बातचीत बंद करने पर भी कुछ समय बाद वापस वसीम ने फोन किया और रतलाम में अल्कोहल प्लांट के समीप मिलने बुलाया। वहां जाने पर वसीम ने धमकी दी कि घर वालों को पता चल गया है अब शादी करना पड़ेगी और मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ेगा। इस पर उसने इस घटना की जानकारी मां को दी और फिर पुलिस थाने पर रिपोर्ट करवाई।

बालिकाओं ने हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वूमेन अंतर्गत बनाई मानव श्रंखला

माही की गूंज, शाजापुर।

भारत सरकार द्वारा 2 से 12 सितम्बर 2025 तक हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वूमेन अंतर्गत बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओ एवं कानूनों के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए 10 दिवसीय विशेष जागरूकता शिविरों के आयोजन करने के प्राप्त निर्देशों के परिपालन में जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री संजय त्रिपाठी के मार्गदर्शन में आज शासकीय हायर सेकंडरी विद्यालय ग्राम पनवाड़ी में संकल्प हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वूमेन के अंतर्गत बालिकाओं व महिला केंद्रित योजनाओं व नीतियों पर विशेष क्षमता निर्माण जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

पर्यवेक्षक श्रीमती अमिता माथुर द्वारा बालिकाओं को स्वास्थ्य एवं पोषण की जानकारी देते हुए बताया कि, खान-पान संतुलित पोषण युक्त रहे, इसके लिए तिरंगा थाली व इन्द्रधनुष रंगों के भोज्य पदार्थों दैनिक जीवन में अवश्य सम्मलित करना चाहिए ताकि बालिकाए एनीमिक ना हो। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध आयरन युक्त खाद्यान जैसे मौसमी फल पपीता, कैले, अमरुद एवं खाने के साथ प्रोटीन युक्त दाले एवं दूध से बने पदार्थ के साथ ही मोटे अनाज ज्वार, मक्का व सोयाबीन का सेवन अनिवार्य करें। साथ ही माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के बारे में प्रचलित भ्रांतिया दूर कर नियमित दिनचर्या के साथ पढ़ाई पर फोकस करने की समझाइश दी गई। इस दौरान उपस्थित सामाजिक कार्यकर्ता श्री देवेन्द्र गोठी द्वारा चाइल्ड लाइन के बारे में बताते हुए बच्चों के अधिकार जीने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, विकास का अधिकार एवं सहभागिता के अधिकार के बारे में जानकारी दी गई।

महिला एवं बाल विकास सहायक संचालक सुश्री नीलम चौहान द्वारा बालिकाओं को सुरक्षित व असुरक्षित स्पर्श के बारे में बताते हुए लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की जानकारी दी गई। साथ ही वन स्टॉप सेंटर एवं हब फार वुमेन इम्पावरमेंट के तहत बालिकाओं-महिलाओं को विभिन्न अधिनियम जैसे कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की जानकारी देते हुए किशोर न्याय अधिनियम के बारे में बताया एवं बाल विवाह न हो, इसके लिए विभिन्न फोरम पर जैसे महिला एवं बाल विकास का परियोजना कार्यालय, नजदीकी थाने व चाइल्ड हेल्प लाइन 1098 पर शिकायत दर्ज कर सकते है एवं साइबर अपराध से बचाओ के लिए टोल फ्री नंबर 1930 एवं पॉक्सो-ई-बॉक्स के बारे में जानकारी प्रदान की। इस दौरान बालिकाओं द्वारा हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वूमेन की मानव श्रंखला भी बनाई गई।

इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ से श्री मणिशंकर वर्मा, श्रीमती माया आर्य, श्रीमती डॉली सिंह, श्रीमती राधा नागदिया, श्रीमती सादिका कुंवर, सुश्री दिव्या पाटीदार, महिला एवं बाल विकास से आंगनवाडी कार्यकर्ता श्रीमती हेमलता मेवाडा, श्रीमती संगीता आर्य एवं विद्यालयीन बालिकाएं एवं परिजन उपस्थित थे। कार्यक्रम में आभार विद्यालय प्राचार्य क्रांतिविजय खेनवार ने माना।

मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने किया स्थलों का निरीक्षण

माही की गूंज, मंदसौर।

प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का 12 सितंबर को प्रस्तावित मल्हारगढ़ एवं गांधी सागर का भ्रमण कार्यक्रम है। इसी क्रम में कलेक्टर अदिती गर्ग एवं पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीना ने मंगलवार को शासकीय महाविद्यालय मल्हारगढ़ एवं गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर एवं एसपी ने हेलीपैड स्थल, पार्किंग व्यवस्था, बैरिकेडिंग, मंच, आमसभा स्थल की तैयारी और सुरक्षा व्यवस्था का विस्तार से अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी व्यवस्थाएँ समय रहते पूर्ण होनी चाहिए ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो।

कलेक्टर ने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि, विद्युत विभाग कार्यक्रम के दौरान विद्युत आपूर्ति सुचारू रखें। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करे। स्वच्छता एवं नगर निकाय विभाग कार्यक्रम स्थल पर साफ-सफाई एवं चलित शौचालय की व्यवस्था करे। पुलिस विभाग यातायात व्यवस्था, पार्किंग एवं सुरक्षा प्रबंधन को व्यवस्थित रूप से लागू करे। एसडीईआरएफ एवं गोताखोर दल को तैनात करने के निर्देश दिए गए ताकि जल क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी स्पष्ट रूप से लगाई जाए तथा समय पर उपस्थित रहना अनिवार्य किया जाए। निरीक्षण के दौरान सीईओ जिला पंचायत अनुकूल जैन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेरसिंह बघेल, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश दीक्षित सहित ब्लॉक स्तरीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

पिता-पुत्र का मंदिर...जहां आमने-सामने बैठे है शिव और गणेश

माही की गूंज, मंदसौर।

शहर के मल्हारगंज क्षेत्र में पुलिस थाने के सामने स्थित सिद्धि विनायक छोटा गणेश मंदिर 200 वर्ष पुराना है। यह गणेश मंदिर मध्य क्षेत्र के नागरिकों की आस्था का केंद्र है। तात्या की बावड़ी के अग्र भाग में यह मंदिर है। इसी परिसर में सरकारी लाल अस्पताल भी है। छोटा गणेश मंदिर विट्ठल महादेव किबे (तात्या जोग) द्वारा बनवाया गया था। वर्तमान में हेरंब (गणेश जी का एक नाम) ट्रस्ट इसकी व्यवस्था का दायित्व निभा रहा है।

किबे गणपति के नाम पर करते थे कारोबार

मल्हारगंज की स्थापना महाराजा मल्हारराव होल्कर द्वितीय के नाम पर की गई थी। यहीं तात्या परिवार के गणेश दास कृष्ण किबे गणपति के नाम पर ही अपना व्यापार व्यवसाय करते थे। गणेशजी किबे परिवार के ईष्ट देवता हैं। गणेश दास कृष्ण होल्कर रियासत के 11 पंचों में से एक थे। उनकी व्यापारिक फर्म का नाम गणेश दास कृष्ण जी था। यह देश भर में कारोबार करती थी। इस फर्म का कारोबार चीन तक फैला था। प्राचीन दौर में गणेशदास कृष्ण किबे को व्यापारियों का राजा भी कहा जाता था।

मल्हारराव द्वितीय ने दी थी यह जमीन

1818 की मंदसौर संधि के पश्चात महाराजा मल्हारराव होल्कर द्वितीय ने विट्ठल महादेव किबे को उनके विशिष्ट योगदान के लिए मल्हारगंज क्षेत्र की यह भूमि प्रदान की थी। तात्या जोग ने इस स्थान पर एक भव्य बावड़ी का निर्माण कराया था। यह बावड़ी तात्या की बावड़ी के नाम से पहचानी जाती है। वर्तमान में इस बावड़ी को बंद कर रखा है। इस बावड़ी में अटूट पानी था। नगर निगम के टैंकर यहां से पानी भर कर शहर में सप्लाई किया करते थे। तात्या की बावड़ी मशहूर है।

दर्शन से ठीक होते मनारोग और पीलिया

किसी समय इस क्षेत्र को गणेश बाग भी कहा जाता था। श्रद्धालुओं की ऐसी मान्यता थी कि इस मंदिर के दर्शन से मनोरोग और पीलिया तुरंत ठीक हो जाता है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि पिता पुत्र अर्थात शंकर महादेव और श्री गणेश दोनों की ही मूर्तियां आमने-सामने हैं। इसलिए इस मंदिर को पिता-पुत्र का मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर में गणेश जी की मूर्ति आकर्षक है। शिवलिंग भी सुंदर है। यहां स्थापित सिद्धिविनायक गणपति की बाई सूंड की पाषाण प्रतिमा करीब 4 फीट की है। गणेश जी की प्रतिमा के समीप ही रिद्धि सिद्धि विराजित हैं।

विट्ठल महादेव किबे ने मंदसौर संधि में निभाई थी अहम भूमिका

विट्ठल महादेव किबे को तात्या जोग के नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म 1778 में खानदेश महाराष्ट्र में हुआ था। 1818 में अंग्रेजों से मंदसौर में हुई संधि में विट्ठल महादेव किबे की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्हीं के प्रयासों से यह संधि हो पाई थी। इसी संधि की शर्तों के अनुसार इंदौर होल्कर राज्य की राजधानी बना और छावनी क्षेत्र के रेजीडेंसी एरिया में अंग्रेज अधिकारियों के लिए पृथक भूमि प्रदान की गई। जहां एजेंट-टू-गवर्नर जनरल का मध्य भारत का मुख्यालय हुआ करता था।

कुशल प्रशासक थे किबे, बढ़ाई थी होल्कर रियासत की आय

विट्ठल महादेव किबे कुशल प्रशासक थे। वे मल्हारराव होल्कर द्वितीय (कार्यकाल 1811-1833) के विश्वसनीय सलाहकार भी थे। होल्कर राज्य की 1817 में कुल आय 5 लाख रुपये थी, जिसे किबे साहब ने अपने प्रयासों के माध्यम से 27 लाख रुपये तक पहुंचा दी थी। महिदपुर युद्ध में अंग्रेजों से सुलह करवाने में भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इस कारण महाराजा ने तात्या जोग को 20 हजार रुपये वार्षिक की जागीर प्रदान की थी। 1826 में आपका निधन हो गया। लार्ड हेस्टिंग ने तात्या जोग के बारे में लिखा- 'एक बुद्धिमान और श्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। होल्कर के साथ संधि करने में मुझे अच्छा लगा। वर्तमान में छावनी इलाके में किबे कंपाउंड स्थित है। किबे परिवार का प्राचीन निवास आज भी इसी क्षेत्र में दवा बाजार के सामने स्थित है। इसमें तात्या के परिवार के अजय किबे निवास करते हैं।

देर रात स्टेशन के नजदीक मालगाड़ी पटरी से उतरी

माही की गूंज, खंडवा।

मंगलवार रात 9 बजकर 33 मिनट पर खंडवा रेलवे जंक्शन के पास दिल्ली-मुंबई मार्ग पर एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। मालगाड़ी की कुछ बोगियों के पहिए पटरियों से उतर गए और एक बोगी का हिस्सा हवा में लटक गया। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारियों ने भुसावल और मुंबई मुख्यालय को जानकारी दी और कई ट्रेनों को मार्ग में रोकना पड़ा। लगभग चार घंटे की मशक्कत के बाद मालगाड़ी को ट्रैक से हटाया गया और यातायात बहाल हो सका।

मालगाड़ी भुसावल से इटारसी की ओर जा रही थी। हादसा खंडवा रेलवे जंक्शन के नजदीक कब्रिस्तान रोड स्थित रेलवे केबिन के पास हुआ। अचानक बोगियों के पहिए पटरी से उतर गए और एक बोगी का हिस्सा हवा में झूल गया। सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू करवाया।

रेलवे पुलिस के मुताबिक, मालगाड़ी पटरी से उतरने के चलते लगभग चार घंटे का ब्लॉक लिया गया। रात 9 बजकर 36 मिनट से 1 बजकर 33 मिनट तक यातायात बंद रहा। इस दौरान 12 ट्रेनें प्रभावित हुईं। सबसे पहले सचखंड एक्सप्रेस को 1 बजकर 41 मिनट पर निकाला गया।

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि मालगाड़ी के पहिए पटरी से क्यों उतरे, यह जांच का विषय है। घटना की रिपोर्ट रेलवे मुख्यालय को भेज दी गई है। फिलहाल स्थिति सामान्य है और मार्ग पर ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो गई है।

2 बच्चों की मां ने लगाई फांसी

माही की गूंज, खंडवा।

खंडवा के आनंद नगर क्षेत्र स्थित सिंगाजी नगर में मंगलवार देर रात एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 39 वर्षीय अर्चना साकल्ले का शव उनके घर के रसोईघर में दुपट्टे से लटका हुआ मिला। घटना की जानकारी तब हुई जब सुबह उनका 12 वर्षीय बेटा पानी पीने के लिए उठा। बेटे ने मां को फंदे पर लटका देखा तो रोते हुए पिता के पास पहुंचा और उन्हें जगाया।

पुलिस के अनुसार, अर्चना साकल्ले के पति एक निर्माण कंपनी में काम करते हैं। महिला ने फांसी लगाने के लिए दुपट्टे का इस्तेमाल किया। रामेश्वर पुलिस चौकी प्रभारी सुभाष नावड़े ने बताया कि मौके से कोई आत्महत्या पत्र बरामद नहीं हुआ है। प्रारंभिक जांच में पारिवारिक कलह की आशंका जताई जा रही है, लेकिन आत्महत्या के सही कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। मृतका के दो बच्चे हैं, जिनकी उम्र 12 और 6 साल है। घटना के बाद से दोनों बच्चे सदमे में हैं। पुलिस ने जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराया और परिजनों को सुपुर्द कर दिया। मर्ग कायम कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। महिला का मायका उत्तर प्रदेश के झांसी में है। फिलहाल मायके पक्ष की ओर से कोई आरोप नहीं लगाया गया है। मर्ग जांच के दौरान परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों से पूछताछ की जाएगी।

टपकती छत वाले भवन में पढ़ने को मजबूर 36 बच्चे

माही की गूंज, बड़वानी।

बड़वानी जिले के पानसेमल विकासखंड के कुमारिया फलिया प्राथमिक विद्यालय की हालत चिंताजनक है। विद्यालय की छत से पानी टपकता है। भवन की नींव एक तरफ से खोखली हो चुकी है।

विद्यालय में 36 बच्चे पंजीकृत हैं। छत से टपकते पानी को रोकने के लिए तिरपाल का उपयोग किया जा रहा है। बरसात के दिनों में पानी की टपकन रोकने के लिए कई जगहों पर बर्तन रखे जाते हैं।

विद्यालय के शिक्षक अनिल पटेल ने बताया कि पिछले दो वर्षों से वे जनशिक्षक को इस समस्या की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। हर साल विद्यालय को मिलने वाली 10 हजार रुपये की राशि से भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ।

ग्रामवासी नाहरसिंह ने बताया कि विद्यालय में पदस्थ शिक्षकों द्वारा कोई मरम्मत नहीं कराई जा रही है। बच्चे जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर हैं। इस स्थिति में न तो बच्चों को सुरक्षित वातावरण मिल पा रहा है और न ही शिक्षा का अनुकूल माहौल।

मुस्लिम महिलाओं का थाने में धरना

माही की गूंज, बड़वानी।

सेंधवा के जोगवाड़ा रोड स्थित घोड़ेशाह वली मोहल्ले की मुस्लिम महिलाएं बुधवार को शहर थाने पहुँचीं। महिलाओं ने पुलिस पर शिकायत नहीं सुनने का आरोप लगाते हुए धरना दिया।

महिलाओं ने बताया कि 8 सितंबर को मोहल्ले में छेड़छाड़ की घटना हुई, जिसकी जानकारी आसपास के लोगों को नहीं थी। कुछ युवक मोटरसाइकिल से मोहल्ले में आए और गाली-गलौज करने लगे। उन्होंने जान से मारने और घरों में आग लगाने की धमकी भी दी। घटना के समय मोहल्ले में ज्यादातर महिलाएं मौजूद थीं।

महिलाओं का कहना है कि उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के बजाय केवल आवेदन देने की बात कही। इससे नाराज़ होकर मुस्लिम महिलाएं और पुरुष थाने पहुँच गए। शहर थाना प्रभारी बलजीत सिंह बिसेन ने बताया कि उस दिन एक अन्य घटना भी हुई थी। दोनों मामलों की जाँच की जाएगी। उन्होंने शिकायत न सुनने के आरोप को गलत बताया। वरिष्ठ अधिकारियों ने भी शिकायत सुनी है। अधिकारियों से मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। थाना प्रभारी ने साफ कहा कि अगर किसी ने घटना को अंजाम दिया है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

एससी-एसटी विद्यार्थियों ने लैपटॉप हेतु पात्रता अंक घटाने की रखी मांग

माही की गूंज, खरगोन।

खरगोन में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों ने युवा छात्रसंघ के बैनर तले रैली निकाली। छात्रों ने एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम 10 सूत्रीय मांगपत्र सौंपा। संगठन के जिलाध्यक्ष भागीरथ खतवासे के अनुसार विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

मांगपत्र में छात्रवृत्ति प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने की मांग की गई है। छात्रों की प्रमुख मांगों में एमपीटीएएएस पोर्टल की तकनीकी खामियों को दूर करना, जिले में छात्रवृत्ति निगरानी समिति का गठन करना, छात्रवृत्ति संबंधी शिकायतों के लिए निशुल्क हेल्पलाइन, ईमेल और संदेश आधारित समाधान तंत्र विकसित करना शामिल है।

छात्रावासों में सीटें बढ़ाने की मांग भी की गई है। जिले में दो वर्षों से लंबित छात्रवृत्ति और इंदौर नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थियों की पिछले साल से लंबित छात्रवृत्ति तुरंत जारी करने की अपील की गई। साथ ही, लैपटॉप वितरण योजना में एससी-एसटी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पात्रता अंक 75 प्रतिशत से घटाकर 60 या 65 प्रतिशत करने की मांग की गई है। इससे अधिक विद्यार्थियों को योजना का लाभ मिल सकेगा।

बिजासन घाट में कंटेनर हादसा

माही की गूंज, बड़वानी।

सेंधवा से 16 किलोमीटर दूर मुंबई-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिजासन घाट में बुधवार सुबह एक कंटेनर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह घटना सुबह लगभग 9 बजे हुई।

कंटेनर चालक संजू, जो उत्तर प्रदेश के जौनपुर का रहने वाला है, बनारस से शीतल पेय लेकर पुणे (महाराष्ट्र) जा रहा था। बिजासन घाट पर पुलिस चौकी के सामने अचानक वाहन खराब हो गया।

चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए आगे चल रहे वाहनों को बचाने के लिए कंटेनर को सड़क किनारे उतार दिया। हादसे में कंटेनर की बॉडी क्षतिग्रस्त हो गई और अंदर रखे शीतल पेय भी गिर गए।

दुर्घटना में चालक केबिन में फंस गया। पुलिस और ग्रामीणों ने लगभग 30 मिनट की मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला। चालक को मामूली चोट आई।

घटना के कारण कुछ समय तक यातायात प्रभावित हुआ। हालांकि, पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर यातायात को सुचारू कर दिया। कंटेनर अनियंत्रित होकर महाराष्ट्र जा रही एक बस से भी टकरा गया, लेकिन सौभाग्य से बस में सवार किसी भी यात्री को कोई चोट नहीं आई।

रामधाम खेडापा के उत्तराधिकारी संत श्री गोविन्दराम जी शास्त्री का मंगल प्रवेश

माही की गूंज, रतलाम। रामस्नेही संप्रदाय के श्री रामधाम खेडापा के उत्तराधिकारी संत श्री गोविन्दराम जी शास्त्री नर्मदानगर में चातुर्मास करने के बाद अपने सैकडों शिष्यों के साथ रतलाम पधारे। संत श्री के मंगल प्रवेश के मार्ग में जगह जगह उनका पुष्पवर्षा कर स्वागत किया गया। वहीं कालिका माता मन्दिर से भव्य शोभायात्रा निकाली गई,जिसमें बडी संख्या में श्रद्धालुजन शामिल हुए।

संत श्री गोविन्दराम जी शास्त्री ने अपने सैकडों शिष्यों के साथ रतलाम में प्रवेश किया। करीब पचास चार पहिया वाहनों का उनका काफिला सबसे पहले फौव्वारा चौक पर पंहुचा,जहां पुष्पवर्षा कर उनका स्वागत किया गया। संत श्री का काफिला वहां से स्टेशन रोड और कोर्ट तिराहे से होते हुए कालिका माता पंहुचा।

कालिका माता मन्दिर में संत श्री ने कालिका माता के दर्शन किए। कालिका माता परिसर से संत श्री गोविन्दराम जी को रामद्वारा तक ले जाने के लिए भव्य शोभायात्रा का आयोजन किया गया था। संत श्री एक खुली बग्गी में आसीन थे। शोभायात्रा में सबसे आगे महिलाएं मंगल कलश धारण कर चल रही थी। बैण्ड और ढोल ढमाकों के बीच संत श्री के शिङ्ष्य नाचते हुए चल रहे थे। श्री बडा रामद्वारा पंहुचने पर रामद्वारा के महन्त पुष्पराज रामस्नेही ने संत श्री का आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर रामद्वारे के उत्तराधिकारी संत ध्यानदास रामस्नेही समेत अनेक संत वृन्द भी मौजूद थे।

संत श्री गोविन्दराम जी के रतलाम पंहुचने पर रामद्वारे के मार्ग के बीच अनेक स्थानों पर पुष्पवर्षा कर उनका स्वागत किया गया। सबसे पहले फौव्वारा चौक पर रामद्वारा ट्रस्ट के ट्रस्टी समाजसेवी गोविन्द काकानी, संजीत परिहार समेत अनेक लोगों ने संत श्री के काफिले पर पुष्पवर्षा की। संत श्री का काङ्फिला जब स्टेशन रोड से गुजरा तो रामद्वारा बिल्डिंग के सामने समाजसेवी अनिल बरमेचा, अमित लामा, रामद्वारा ट्रस्ट के ट्रस्टी तुषार कोठारी वएडवोकेट दशरथ पाटीदार,एडवोकेट संतोष त्रिपाठी समेत बडी संख्या में मौजूद लोगों ने संत श्री पर पुष्पवर्षा कर उनका अभिनन्दन किया।

हर आपदा के समक्ष जरूरी राष्ट्र की एक जुटता

चुनाव कोई भी होकृसंसदीय, विधानसभा, नगरपालिका या पंचायतकृ उसे लड़ने की तैयारी की शुरुआत ढेरों बैठकों (संसदीय समितियां, कार्यसमितियां, चुनाव समितियां आदि) बनाने से की जाती है। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति और बूथ स्तर तक चुनाव प्रबंधकों को काम पर लगाया जाता है; केंद्रीय नेता राज्यों में, राज्य के राजनेता ज़िलों में और ज़िला स्तरीय नेता पंचायतों में जाकर प्रचार करते हैं। चुनावी उत्सव लासानी रणनीति के साथ लड़ा जाता है दृ वॉर रूम बनाना, कार्यकर्ताओं को लामबंद करना, अद्भुत कंप्यूटिंग शक्ति और डेटा से लैस चुनाव विश्लेषकों की तैनाती। वहीं इन दिनों नौकरशाही भी खुलकर शामिल हो रही है और अंततः हमको चुनाव में सक्रिय हुए बेहतरीन और प्रतिभावान लोग देखने को मिलते हैं। बेशक, यह सब धन और भौंडेपन के प्रदर्शन के साथ होता है, जो अपने पिछले सर्वश्रेष्ठ से हमेशा एक कदम आगे ही होता है।

मुद्दा यह कि सभी दलों का नेतृत्व पूरी तरह सक्रिय दिखाई-सुनाई देता है। अगर चुनावों के लिए इस स्तर का प्रबंधन संभव है और इतनी बड़ी मात्रा में धन का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में लगातार जारी बाढ़ के बीच लाखों लोग क्यों दुख में डूबे हुए हैं?

नदियां और पहाड़ी नाले उफान पर हैं, हर तरफ भूस्खलन हो रहा है, सड़कें बह गई, पुल ढह रहे हैं, बांधों-नहरों के कुप्रबंधन के आरोप लग रहे हैं- पूरा सिविल ढांचा चरमराया पड़ा है। प्रकृति का कोप हर ओर दिखाई देता है, लेकिन नागरिक प्रशासन का मरहम लगाने वाला हाथ कहने भर को सक्रिय है।

बाढ़ बिना किसी अच्छी खासी पूर्व सूचना के नहीं आती; खासकर इस बार मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान सटीक रहा। जुलाई, अगस्त, और सितंबर में भारी बारिश का पूर्वानुमान दिया थादृ फिर भी समय रहते संगठित प्रतिक्रिया का अभाव रहा। राज्य सरकारें कहती है, उन्होंने ऐसी आकस्मिकताओं के लिए बाकायदा दिशा निर्देश तय किये हैं। लेकिन, उन्हें लागू करने का जिम्मा किसका?

क्या यह व्यक्तिगत या संगठनात्मक विफलता थी, या इन राज्यों की सरकारों की सामूहिक विफलता? क्या रिकॉर्ड में कुछ दर्ज है? बताएं क्या कोई तैयारी पहले की थी, कोई अभ्यास किया, क्या अधिक आपदा की आशंका वाले इलाके चिन्हित किये थे? क्या ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त कार्यबल, सामग्री और अन्य संसाधन उपलब्ध थे? क्या इसके लिए अधिकारी नियुक्त किए गए? क्या ज़िला व राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए व उनका परीक्षण किया? बांधों से अतिरिक्त पानी छोड़े जाने की स्थिति में निचले इलाकों के गांवों के लिए चेतावनी प्रणाली क्या थी? यकीनन, इन सवालों के अधिकतर जवाब नेगेटिव या अस्पष्ट ही होंगे।

फिर, बाढ़ आने के बाद प्रतिक्रिया क्या रही? क्या यह संस्थागत प्रतिक्रिया थी या फिर अक्ल और निष्ठा की काबिलियत से युक्त अधिकारियों की बेतरतीब प्रतिक्रिया रही? समाचारों के अनुसार, अधिकांशतः निराशा भरे इस माहौल में कुछ उजले बिंदु भी दिखाई दिये। मैंने सरकारी बचाव नौकाएं चलाए जाने की ज्यादा बात नहीं सुनी और आसमान में किसी भी तरह की बचाव हलचल नहीं दिखी, सिवाय एकाध हेलीकॉप्टर के। सूबे में केंद्रीय बल और सेना हर तरफ उपलब्ध है और ऐसी आकस्मिकता के दौरान नागरिक प्रशासन की मदद को उन्हें बुलाया जा सकता है। सेना की कुछ टुकड़ियां खासकर ऐसे उद्देश्यों के लिए तय होती हैं, और सिविल अधिकारियों को उनके साथ संपर्क बनाए रखना होता है।

मूल बात यह कि ऐसी वार्षिक आपदाओं का सामना करने के लिए योजनाएं पहले से बनाकर तैयारी रखी जानी चाहिए थी, खासकर जब मौसम विभाग का पूर्वानुमान इतना सटीक हो। सार्थक सरकारी प्रतिक्रिया के अभाव में, यह काम नागरिक समाज पर छोड़ दिया गया क्योंकि उनका जीवन व आजीविका प्रकृति के कोप से बचाव करने पर टिका है। ग्रामीणों ने तात्कालिक समस्याओं से लड़ने को खुद को संगठित किया। उन्हें अपने परिवार, घर, पशुओं को बचाना था - उन्हें भजन गाते हुए अपने भरोसे आपदा से जूझते देखना दिलासा देने वाले रहा। ऐसे लोगों को हमें किसी राष्ट्रीय धरोहर की तरह संजोकर रखना चाहिए- ऐसे मानव संसाधन आसानी से नहीं मिलते।

क्या हमेशा की तरह यह आपदा भी तुच्छ राजनीति और तस्वीरें खिंचवाने का मौका है? क्या हम एक राष्ट्र के रूप में इस अवसर पर खड़े नहीं हो सकते? 'राज्य', जब संगठित हो, तो संसाधन विशाल बन जाते हैं और जबरदस्त कारनामे करने में सक्षम होता है। नेतृत्व का अर्थ है लोगों को प्रेरित करना और संसाधनों का समन्वय करना - 'आपदा की घड़ी बने, तो अगुवा सबसे आगे लगे'। यहां वह व्यक्ति कहां है जो राष्ट्र की विशाल जनशक्ति को संगठित कर सके? या फिर क्या हम 'निम्न दर्जा नेताओं व खोखले लोगों' का पिछलग्गू बनने को अभिशप्त हैं? हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान हम सबके लिए एक मिसाल है, हम उस स्वतंत्र भारत की संतान हैं जिसमें अत्याचारों का कोई स्थान नहीं। क्या हमें अपने ही लोगों द्वारा लूटा जाना चाहिए?

आज देश के अंदर से और हमारी दुश्मन ताकतों की ओर से बहुत शरारतें हो रही हैं - टैरिफ के रूप में भू-राजनीतिक चुनौतियों से लेकर पाकिस्तान की धमकियां और उसके पाले-पोसे आतंकवाद से लेकर हमारे अन्य पड़ोसियों के निहित स्वार्थों तक। जलवायु परिवर्तन खुद में एक आपदा है। ऐसे समय हम एकजुट होकर सामना करें। यदि आज पंजाब और हिमाचल इसका खमियाजा भुगत रहे हैं, तो कल दक्षिण या पश्चिम भारत में भी ऐसा कुछ घट सकता है। राष्ट्र एकजुट होकर प्रतिक्रिया देना सीखे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को युद्धस्तर पर पुनर्वास की जरूरत होगी। घर, खेत, पशुधन, उपकरण नष्ट हो गए, साथ ही आजीविका के साधन भी। सरकार और नागरिक समाज को तबाही का तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और समन्वित प्रतिक्रिया देनी चाहिए।

आज, पश्चिमी दुनिया के अधिकांश हिस्से में अति-दक्षिणपंथी विचारधारा का पुनरुत्थान हो रहा है, और इसकी सीमाओं पर तनाव बढ़ा है। जिन युवाओं ने विदेश में अच्छे भविष्य की उम्मीदें लगायी थीं, वे शायद उस मृगतृष्णा को फीका पड़ता पाएंगे और उनमें कई खुद ही वापसी की फ्लाइट पकड़ते दिख सकते हैं या फिर 'पश्चिम जाने' से खुद को वंचित किए जाते पाएंगे। उन्हें यहां देश में ही अवसर ढूंढ़ने होंगे और महान राष्ट्र के निर्माण का हिस्सा बनना होगा।

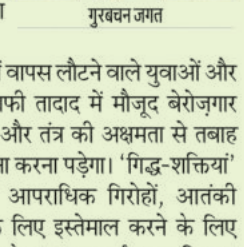

गुरबचन जगत

बड़ी संख्या में वापस लौटने वाले युवाओं और पहले ही यहां काफी तादाद में मौजूद बेरोज़गार युवाओं को बाढ़ और तंत्र की अक्षमता से तबाह हुए देश का सामना करना पड़ेगा। 'गिद्ध-शक्तियां' इन युवाओं को आपराधिक गिरोहों, आतंकी संगठनों आदि के लिए इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। सरकार के समक्ष पुनर्वास का विशाल कार्य होगा और उसे बेरोज़गार युवाओं की बड़ी संख्या को साथ लाने के लिए एक योजना बनानी होगी। इसके लिए चुनिंदा युवाओं, प्रतिभाशाली नौकरशाहों और कॉर्पोरेट जगत के लोगों को मिलाकर बनाए गए एक केंद्रीय कार्य समूह को यह काम सौंपा जाए और उनकी सिफारिशें तुरंत लागू की जाएं। नेताओं को भी इस प्रयास में वही ऊर्जा व नवीनता लानी पड़ेगी जैसी चुनाव में लगाते हैं।

एक अंतिम टिप्पणी- जलवायु परिवर्तन मुंह बाए खड़ा है, चाहे डोनॉल्ड ट्रम्प इस पर विश्वास करें या नहीं। विज्ञान इस ओर स्पष्ट इशारा कर रहा है, और हम ज़मीनी स्तर पर इस बदलाव के परिणाम देख-झेल रहे हैं। हम पहले ही बहुत देर कर चुके हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ बचाया जा सकता है। क्या मानव जाति एक बार फिर एकजुट होकर आसन्न सर्वनाश से खुद को बचा पाएगी?

महिला कॉन्स्टेबल का राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार

माही की गूंज, उज्जैन

नगर में महिला कॉन्स्टेबल (आरक्षक) का बुधवार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया। हादसे के तीन दिन बाद कॉन्स्टेबल का शव शिप्रा नदी से बरामद हुआ था। इसी के साथ बड़े पुल पर हुए हादसे के मामले चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है।

बता दें कि शनिवार रात 8:55 बजे जूना सोमवारिया से बड़नगर रोड पर जा रही कार पुल से नदी में गिर गई थी। घटना के पांच घंटे बाद पता चला कि कार में उन्हेल टीआई अशोक शर्मा, एसआई मदनलाल निनामा और आरक्षक आरती पाल थे। शर्मा और निनामा के शव सोमवार को मिल गए थे, लेकिन कॉन्स्टेबल आरती का शव और कार मंगलवार को मिली।

इसके बाद आरती का बुधवार को पोस्टमॉर्टम कराया गया और चक्रतीर्थ पर अंतिम संस्कार कर दिया, जहां पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया था। वहीं, एडीजीपी उमेश जोगा, डीआईजी नवनीत भसीन, एसपी प्रदीप शर्मा ने सैल्यूट किया। मौकेपर कलेक्टर रोशन कुमार सिंह और नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा भी मौजूद थे। इस दौरान कई पुलिसकर्मी अपने आंसू नहीं रोक पाए।

हादसे के लिए प्रशासन जिम्मेदार

हादसा जीवजीगंज थाना क्षेत्र में हुआ था। इस क्षेत्र में बड़ा पुल, ऋणमुक्तेश्वर, विक्रांत भैरव, काल भैरव और गंगा तीर्थ पुल पर रेलिंग, स्ट्रीट लाइट और संकेतक नहीं हैं। यहां हादसे होने की आशंका को लेकर टीआई विवेक कनोड़िया ने इनकी व्यवस्था कराने के लिए प्रशासन को पत्र लिखा था। यही नहीं टीआई कनोड़िया ने घटना से 10 घंटे पहले तहसीलदार रूपाली जैन को वॉट्सऐप कर बताया था कि गणेश विसर्जन पर व्यवस्था नहीं होने से कोई अनहोनी की संभावना है। फिर भी सुधार नहीं हुआ और तीन पुलिस कर्मियों की जान चली गई।

क्यों हटाई गई रेलिंग?

घटना की सबसे बड़ी वजह पुल पर स्ट्रीट लाइट और रेलिंग नहीं होना माना जा रहा है। इस संबंध में पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के अनुसार, दो तरह के ब्रिज होते हैं। हाई राइज ब्रिज से रेलिंग, लाइट नहीं हटाई जाती, जबकि डूब क्षेत्र के पुल पर 15 जून से अक्टूबर तक रेलिंग हटाने का नियम है। इसलिए पुल पर एक माह ऐर रेलिंग नहीं लगाई जा सकती। लोगों को सचेत करने के लिए संकेतक, रिफ्लेक्टर, रेडियम या झंडे लगाना चाहिए। हालांकि अब निगमायुक्त अभिलाष मिश्रा ने इंतजाम करने के निर्देश दे दिए हैं।

घटनाक्रम एक नजर में

6 सितंबर (शनिवार) रात 8:55 बजे बड़े पुल से कार नदी में गिरी. 9:30 बजे तलाश शुरू

6-7 सितंबर, रात 2 बजे पता चला कार में उन्हेल एसओ अशोक शर्मा, एसआई मदनलाल निनामा और आरक्षक आरती पाल थे। तीनों 4 सितंबर को लापता हुई लड़की की तलाश करने चिंतामण क्षेत्र में जा रहे थे।

7 सितंबर, सुबह 9 बजे एसओ शर्मा का शव करीब 5 किमी दूर भैरवगढ़ पुल के नीचे मिला। इसी दिन शाम को राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार किया।

8 सितंबर, सुबह हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया. घटनास्थल से 3 किमी दूर कार का बंपर मिला। शाम 4:30 बजे एसआई निनामा का शव भैरवगढ़ पुल के नीचे मिला।

9 सितंबर की शाम को बड़े पुल के पास मिली कार और उसमें आरती पाल का शव मिला।

10 सितंबर को पोस्टमॉर्टम के बाद आरक्षक आरती पाल का राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार किया।

किसानों की समस्याओं को लेकर होगा विशाल धरना-प्रदर्शन

माही की गूंज, सोंडवा।

किसानों की बिगड़ती स्थिति और प्रशासनिक उदासीनता को लेकर आदिवासी विकास परिषद ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। परिषद के जिला अध्यक्ष अंगर सिंह चौहान ने जानकारी दी कि किसानों की फसलें पीला मोजेक रोग से बर्बाद हो रही हैं। वहीं खाद-बीज की भारी कमी, बिजली आपूर्ति में अव्यवस्था और बंगाली फर्जी डॉक्टरों की बढ़ती गतिविधियों ने ग्रामीण अंचलों को संकट में डाल दिया है।

चौहान ने बताया कि, पुलिस प्रशासन की विफलता और किसानों पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में दिनांक 12 सितम्बर 2025 को सोंडवा ग्राउंड में विशाल धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद परिषद कार्यकर्ता और किसान मिलकर एसडीएम कार्यालय का घेराव कर ज्ञापन सौंपेंगे।

धरना-प्रदर्शन में आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश पटेल एवं जोबट विधायक श्रीमती सेना पटेल विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में सोंडवा ब्लॉक के किसान, ग्रामीण जनता और परिषद कार्यकर्ता भारी संख्या में भाग लेंगे। परिषद पदाधिकारियों ने क्षेत्र के सभी किसानों, युवाओं और आमजन से आह्वान किया है कि वे आंदोलन में शामिल होकर अपनी एकजुटता प्रदर्शित करें।

तेज बारिश के साथ वर्षा ने ली विदाई

माही की गूंज, आम्बुआ।

विगत दिनों से क्षेत्र में हो रही झमा झम बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो रहा था क्षेत्र वासी बारिश थमने की कामना कर रहे थे, खेतों में खड़ी फसलों को भारी नुक्सान हो रहा था, मगर इंद्र देवता मानने को तैयार नहीं थे, आखिर क्षेत्र वासियों की प्रार्थना भगवान ने सुनी और 8 सितंबर की शाम जोर दार बारिश ने एक बार पुनः क्षेत्र को तर-बतर कर दिया। स्थिति ऐसी लग रही थी मानो अब कुछ दिनों तक वर्षा का क्रम बन्द नहीं होगा, मगर आधा घंटे बाद अचानक बारिश थमी और कुछ समय बाद आसमान से बादल विदा होने लगे तथा रात्रि में आसमान पर चांद की छटा एसी बिखरी कि सारा क्षेत्र चांदनी से सराबोर हो गया।

9 सितंबर की सुबह जब सूरज ने भी अपनी सुहानी रोशनी भरी किरणें बिखेरी तब लगा कि शायद बारिश ने बिदाई ले ली। सुबह सूरज की किरणें जैसे ही धरती पर पड़ी तो ओस की मोतियों जैसी घास पर पड़ी बूंदों को देख कर सभी ने यही कहा कि, ओस पड़ने लगी यानि कि वर्षा रानी बिदा हो रही है। दिन भर मौसम साफ बना रहा तथा तेज धूप निकली जिससे फ़सलों को लाभ मिलने की उम्मीद है कृषकों में हर्ष व्याप्त है।

चिराग जैन हत्याकांड का खुलासा

माही की गूंज, इंदौर।

इंदौर के कनाडिया थाना क्षेत्र के मिलन हाइट्स में 23 अगस्त को हुई कारोबारी चिराग जैन की हत्या के मामले में पुलिस ने अहम सफलता दर्ज की है। आरोपी विवेक जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो हत्या के बाद फरार चल रहा था।

क्या हैं पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, विवेक जैन और मृतक चिराग जैन लंबे समय से बिजनेस पार्टनर थे। पहले उनके बीच रिश्ते अच्छे थे, लेकिन कुछ कारणों से उनका आपसी विवाद इतना बढ़ गया कि विवेक ने हत्या का खौफ़नाक कदम उठाया। 23 अगस्त की रात, विवेक जैन चिराग जैन के घर में घुसा और उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया।

हत्या के बाद फरार हुआ आरोपी

हत्या के तुरंत बाद आरोपी फरार हो गया। फरार होने के दौरान विवेक जैन ने उज्जैन, दिल्ली, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, करौली और राजस्थान के कई शहरों में अपनी जगह बदलते हुए पुलिस की पकड़ से बचने की कोशिश की। पुलिस ने लंबे समय तक उसकी तलाश की और अब आखिरकार उसे दबोच लिया गया है।

प्रारंभिक जांच में क्या आया सामने?

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, विवेक जैन की गिरफ्तारी के बाद मामले से जुड़ी कई अहम जानकारी सामने आई है। प्रारंभिक जांच में संकेत मिले हैं कि हत्या के पीछे और भी लोग हो सकते हैं, जिनके खिलाफ आगे की जांच में कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और सभी तथ्यों की छानबीन कर रही है। इस गिरफ्तारी के साथ ही चिराग जैन हत्या कांड में एक बड़ी गुत्थी सुलझ गई है, लेकिन पुलिस का कहना है कि जांच पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है और आगे भी मामले में नए खुलासे हो सकते हैं।

समर्थन मूल्य पर ई-उपार्जन परियोजना 15 सितम्बर से प्रारम्भ

माही की गूंज, अलीराजपुर।

संयुक्त कलेक्टर एवं प्रभारी खाद्य आपूर्ति अधिकारी मनोज गरवाल ने बताया कि, जिले के समस्त पंजीकृत किसान भाईयों को अवगत कराया जाता है कि खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार, बाजरा का उपार्जन ई-उपार्जन परियोजना अंतर्गत दिनांक 15 सितम्बर 2025 से प्रारम्भ होकर पंजीयन दिनांक 10 अक्टूबर 2025 तक किसानों के पंजीयन किये जायेंगे। इस वर्ष सभी किसानों को नवीन पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। पूर्व में कराये गये किसान पंजीयन मान्य नहीं होगें। नवीन पंजीयन कराते समय कृषक निर्धारित आवेदन पत्र के साथ बैंक खाता, आधार नम्बर एवं ऋण पुस्तिका की छायाप्रति संलग्न करेगा। यदि कृषक द्वारा भूमि शिकमी पर ली गई है तो शिकमी अनुबंध-पत्र की प्रति भी प्रस्तुत करना होगा। उन्होने समस्त समस्त पंजीकृत किसान भाईयों से अपील की है कि खरीफ पंजीयन हेतु अपने नजदीकी पंजीयन केंद्र पर धान, ज्वार, बाजरा का उपार्जन ई-उपार्जन परियोजना अंतर्गत दिनांक 15 सितम्बर 2025 से प्रारम्भ होकर दिनांक 10 अक्टूबर 2025 से पूर्व किसान पंजीयन कराना सुनिश्चित करें।

वीरदुर्गादास गरबा मंडल समिति का गठन सम्पन्न

माही की गूंज, अलीराजपुर।

आगामी शारदीय नवरात्रि पर्व को लेकर राठौड़ समाज में खासा उत्साह देखा जा रहा है। इसी कड़ी में राठौड़ समाज धर्मशाला में आयोजित एक सामान्य बैठक के दौरान सर्वसम्मति से वीरदुर्गादास गरबा मंडल समिति का गठन किया गया। बैठक की अध्यक्षता समाज अध्यक्ष महेन्द्र टवली ने की।

बैठक में समाजजनों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस वर्ष भी गरबा महोत्सव को पारंपरिक भव्यता एवं धार्मिक आस्था के साथ मनाया जाएगा। तय किया गया कि गरबा आयोजन प्रतिदिन रात्रि 9:00 बजे से 12:00 बजे तक किया जाएगा। समिति द्वारा बताया गया कि राठौड़ समाज द्वारा बीते 8 वर्षों से यह आयोजन निरंतर सफलतापूर्वक किया जा रहा है, जो अब समाज की एक गौरवपूर्ण परंपरा बन चुका है।

मीडिया प्रभारी कांतिलाल राठौड़ ने बताया कि नवगठित समिति मे अध्यक्ष राजेश सेठ (राठौड़ बस सर्विस), उपाध्यक्ष कृष्णकांत चौधरी, कोषाध्यक्ष बद्रीलाल चौधरी, सचिव सचिन रामेश्वर राठौड़, सह सचिव पवन संतोष राठौड़, मीडिया प्रभारी कांतिलाल राठौड़ को पदाधिकारी नियुक्त किए गए। इसके पूर्व वीर दुर्गादास समिति के कोषाध्यक्ष राहुल राठौड़ ने 2024 का हिसाब पेश किया इसके बाद नवीन समिति का गठन किया गया।

आयोजन की बेहतर व्यवस्था के लिए बनी उप समितियाँ

गरबा आयोजन को सुचारु एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने हेतु विभिन्न उप समितियों का भी गठन किया गया। जिनमें चंदा समिति, चल समारोह समिति, पंडाल व्यवस्था समिति, प्रसादी समिति तथा साउंड समिति प्रमुख रूप से शामिल हैं।

समाजजनों ने लिया सहयोग का संकल्प

बैठक में कांतिलाल पार्षद, श्याम सेंडी, लोकेश राठौड़, राहुल राठौड़, रमेशचंद्र राठौड़, जगदीश राठौड़, जितेन्द्र राठौड़, राघवेंद्र राठौड़, कमलेश चौधरी, यतेन्द्र चौधरी, प्रशांत राठौड़, आशुतोष राठौड़, प्रदीप राठौड़, मोतीलाल राठौड़, जेंतिलाल राठौड़, विजय राठौड़, पवन डायमंड, हितेंद्र राठौड़, कितेंश राठौड़, संदीप राठौड़ सहित समाज के अनेक युवा एवं गणमान्यजनों की उपस्थिति रही।

सभी ने आयोजन को सफल बनाने के लिए तन-मन-धन से सहयोग देने का संकल्प लिया। बैठक में यह भी तय किया गया कि गरबा आयोजन के माध्यम से सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक मूल्यों को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा।

समाज अध्यक्ष महेन्द्र टवली ने सभी समाजबंधुओं को नवरात्रि महोत्सव में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया और कहा कि ÷यह आयोजन न केवल हमारी सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करता है, बल्कि समाज को एकजुट करने का भी सशक्त माध्यम है।

पहले इंदौर, फिर उज्जैन में शुरू होगी सुगम परिवहन सेवा

भोपाल।

मध्य प्रदेश में सुगम परिवहन सेवा प्रारंभ करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने डेडलाइन तय कर दी है। अब हर हाल में मार्च के पहले बसों का संचालन प्रारंभ किया जाएगा।

सबसे पहले इंदौर और इसके बाद उज्जैन से सेवा प्रारंभ की जाएगी। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को मंत्रालय में परिवहन विभाग के कामकाज की समीक्षा की। यहां अधिकारियों ने बताया कि अब यातायात नियम तोड़ने पर चालानी कार्रवाई का अधिकार प्रधान आरक्षक को भी दिया जाएगा।

इस संबंध में शीघ्र ही अधिसूचना जारी होने वाली है। बता दें कि वर्ष 2006 में मप्र राज्य सड़क परिवहन निगम बंद होने के बाद से सार्वजनिक परिवहन की सुविधा नहीं है। परिवहन सचिव मनीष सिंह ने बताया कि उज्जैन जिले में सार्वजनिक बस संचालन का विस्तृत सर्वे पूरा कर लिया गया है। जबलपुर और इंदौर में रूट सर्वे और श्रेणीवार संचालित बसों की संख्या का अनुमान और सर्वे भी लगभग पूरा हो गया है।

वाहनों की स्पीड पर नियंत्रण जरूरी

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अंतरविभागीय बैठक नियमित रूप से हो। सड़कों पर सुरक्षा से जुड़ी कमियां पाए जाने पर उन्हें तत्काल दूर किया जाए। बस स्टाप पर नागरिकों को साफ-सफाई के साथ आवश्यक सुविधाएं मिलें। परिवहन विभाग की राजस्व संग्रह निगरानी प्रणाली को और मजबूत करें। वाहनों की गति सीमा पर नियंत्रण बेहद जरूरी है। इसके साथ गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति के पास आवश्यक कागजों की वैधता की जांच भी नियमित हो। परिवहन विभाग में बेहतर प्रबंधन के लिए अधिकारी-कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर भी जोर दिया।

सुगम परिवहन सेवा में हो कम से कम किराया

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुगम परिवहन सेवा में यात्रियों की सुविधाओं और कम से कम किराये पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसमें इलेक्ट्रिक बसों के उपयोग को प्रोत्साहित करें। परिवहन सेवा के लिए बने नियमों का सख्ती से पालन हो। बसों में शहरों एवं गांवों के नाम सामने के कांच पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किए जाएं।

इसके साथ ही बस स्टाप पर भी गांव और नगरों के नाम लिखे हों। यात्री बसों का बीमा अनिवार्य हो। सभी कार्य नियमों के अंतर्गत हों, पारदर्शिता रहे। दिव्यांग यात्रियों का विशेष ध्यान रखा जाए। बसें फिट हों, स्टाफ का व्यवहार अच्छा हो। अप-डाउनर्स को भी आवश्यक सुविधाएं दी जाएं।

इस वर्ष 16 लाख 60 हजार नए वाहन आए, जिनमें 15 प्रतिशत ईव्ही

बैठक में बताया गया कि इस वर्ष 16 लाख 60 हजार वाहनों का पंजीयन किया गया है। इसमें 2 लाख 58 हजार यानी 15 प्रतिशत इलेक्ट्रिकल वाहन हैं। प्रदेश में आन रोड वाहनों की संख्या एक करोड़ 80 लाख के करीब है। परिवहन से प्राप्त होने वाली राजस्व में पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग छह प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बैठक में राजस्व वृद्धि के किए जाने वाले उपायों पर भी चर्चा की गई।

क्या ऑनलाइन पिंडदान सही...?

माही की गूंज, उज्जैन।

श्राद्ध पक्ष (पितृपक्ष) रविवार से शुरु हो गया है। श्राद्ध कर्म मध्य प्रदेश के उज्जैन में करने का विशेष महत्व माना जाता है। इसी कारण से देश-विदेश से श्रद्धालु अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए यहां पहुंच रहे हैं। कुछ पंडित ऑनलाइन तर्पण करने का दावा कर रहे हैं, तो कुछ ऑनलाइन श्राद्ध को शास्त्र विरोधी बता रहे हैं।

क्यों है 15 दिनों के श्राद्ध?

पंडित अमर डब्बावाला ने बताया कि, इस बार श्राद्ध पक्ष में एक तिथि क्षय होने से कुल 15 दिन के श्राद्ध होंगे। 7 सितंबर 2025, रविवार को कुंभ राशि में चंद्रमा की उपस्थिति में पूर्णिमा से श्राद्ध का आरंभ हुआ। इसी दिन रात्रि में चंद्र ग्रहण भी है, जिसका सूतक काल दोपहर 12:58 बजे से शुरू हो गया। इसलिए पूर्णिमा का श्राद्ध इसी समय तक ही किया गया।

उज्जैन में कब से कब तक चलेगा श्राद्ध 2025?

उज्जैन में 7 से 21 सितंबर तक श्राद्ध पक्ष चलेगा। इस दौरान रामघाट, सिद्धवट और गया कोटा पर हजारों श्रद्धालु पहुंचकर पिंडदान, तर्पण और जल-दान करेंगे।

उज्जैन में तर्पण की इतनी खास मान्यता क्यों?

श्राद्धकर्म करने पूरे देश से श्रद्धालु उज्जैन आते है। इसकी वजह उज्जैन को ÷उत्तर भारत का गया÷ भी कहा जाता है। मान्यता है कि कोटा में भगवान श्रीकृष्ण ने तर्पण किया था। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता ने वनवास के दौरान राजा दशरथ का तर्पण उज्जैन में किया था। माता पार्वती ने सिद्धवट पर वटवृक्ष लगाया था, इसलिए यहां वटवृक्ष पर दूध चढ़ाने की परंपरा है। श्रद्धालु गया कोटा, रामघाट और सिद्धवट पर पिंडदान व तर्पण करने आते हैं।

ऑनलाइन कर्मकांड

श्राद्ध करने कई श्रद्धालु समय अभाव के कारण नहीं आ पाते. ऐसे में ऑनलाइन तर्पण की भी सुविधा है। पंडित राजेश त्रिवेदी ने बताया कि कई श्रद्धालु उज्जैन नहीं आ पा रहे हैं, उनके लिए ऑनलाइन तर्पण की व्यवस्था की गई है। श्राद्ध पक्ष के पहले दिन बुलंदशहर (यूपी) से सुरेंद्र शर्मा और गाजियाबाद से अमर उपाध्याय ने ऑनलाइन तर्पण कर ऑनलाइन दक्षिणा भी दी।

ऑनलाइन श्राद्ध से मुक्ति नहीं - पं. डब्बावाला

पं.अमर डब्बावाला के अनुसार, श्राद्ध के लिए शास्त्र धर्म की परंपरा का पालन करें। वर्तमान में हो रही ऑनलाइन श्राद्ध परंपरा पर कुठाराघात है। यह पद्धति सनातन धर्म की संस्कृति का भाग नहीं है इस पद्धति से की पूजा का मनचाहा फल नहीं मिलता है। इसलिए तीर्थ स्थान, मंदिर जाए आपको लगेगा कोई पूजा की है। अन्यथा यह एक कर्तव्य था, इसलिए कर दिया यह सोच आपको संतुष्ट नहीं कर सकेगी श्राद्ध पक्ष की पूर्णिमा पर खास सामूहिक पिंडदान का आयोजन, पंडित जी ने खास मान्यता बताई।

पितृपक्ष 2025 की सभी तिथि और दिन

शास्त्रों के अनुसार, श्राद्ध पक्ष 2025 का शुभारंभ 7 सितंबर 2025 की सुबह 6 बजे से हो गया है। 18 सितंबर 2025 को पुष्य नक्षत्र, सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का संयोग रहेगा। इस दिन किया गया श्राद्ध सभी कार्यों में सफलता दिलाने वाला माना जाता है और यह योग पितरों को मोक्ष देने वाला होता है। इस वर्ष के श्राद्ध की तिथियां निम्न रूप से हैं:-

7 सितंबर (रविवार) - दिन में 12:58 बजे तक पूर्णिमा का श्राद्ध, इसके बाद चंद्रग्रहण का सूतक शुरू

8 सितंबर (सोमवार) - प्रतिपदा का श्राद्ध

9 सितंबर (मंगलवार) - द्वितीया का श्राद्ध

10 सितंबर (बुधवार) - तृतीया का श्राद्ध

11 सितंबर (गुरुवार) - चतुर्थी का श्राद्ध और कुमार पंचमी का पार्वण श्राद्ध

12 सितंबर (शुक्रवार) - षष्ठी का श्राद्ध

13 सितंबर (शनिवार) - सप्तमी का श्राद्ध

14 सितंबर (रविवार) - अष्टमी का श्राद्ध

15 सितंबर (सोमवार) - नवमी का श्राद्ध

16 सितंबर (मंगलवार) - दशमी का श्राद्ध

17 सितंबर (बुधवार) - एकादशी का श्राद्ध

18 सितंबर (गुरुवार) - द्वादशी का श्राद्ध (यह संन्यासियों का श्राद्ध भी माना जाता है)

19 सितंबर (शुक्रवार)- त्रयोदशी का श्राद्ध (प्रदोष तिथि, मघा श्राद्ध)

20 सितंबर (शनिवार) - चतुर्दशी का श्राद्ध (यह श्राद्ध अपघात या अकाल मृत्यु से मृत व्यक्तियों के लिए किया जाता है)

21 सितंबर (रविवार) - सर्वपितृ अमावस्या - पितृपक्ष का अंतिम दिन।

अपने नाम के विपरीत ईश्वर का काम...?

मामला: शासकीय सड़क भूमि की 20 आरा जमीन नायब तहसीलदार पलकेश परमार ने निजी खाते के नक्शे में बताकर मंदिर, सार्वजनिक मृत कूप व प्रतीक्षालय भी बताया निजी खाते में

- बाजना मार्ग पर सार्वजनिक पुरी गंदगी से भरा दल-दल कुप।

माही की गूंज, खवासा/झाबुआ।

कोई व्यक्ति कितना भी धन या संपत्ति अर्जित कर ले पर फिर भी उसकी किसी कथनी व करनी के चलते उसकी निंदा एक तरफा पूरा गांव करने लग जाए तो यह भी एक बड़ा चिंतन का विषय है। और यह बात कोई शिक्षित या यू कहे की शिक्षा को प्रदान करने वाला एक शिक्षक ही नहीं समझ पाए तो यह भी एक बड़ा चिंतन का विषय है।

वही हमारे माता-पिता व बुजुर्ग पूर्व में अपने बेटे-बेटी का नामकरण किसी ऋषि मुनि या फिर भगवान या किसी महापुरूष के नाम पर नामकरण कर यह सोचा जाता था कि, मेरा पुत्र या पुत्री नाम के अनुरूप समाज में अपना हित छोड़ समाज के हित के लिये कार्य करेगा। और अगर यहां कोई अपने नाम के विपरीत जाकर भी कोई कार्य करता है तो उसकी भिन्न प्रकार की चर्चा भी होना लाजमी है।

कुछ यह स्थिति ग्राम खवासा में रोग्या देवी मंदिर के समीप भूमि के मालिक ईश्वर लाल चौहान जो की एक शिक्षक भी है व उसके सामने पूरे ग्रामवासियो का एक वाकयुद्ध छिड चुका है और मामला न्यायालय में भी पहुंचा है।

मामला यह कि, बाजना मार्ग स्थित रोग्य देवी मंदिर व मंदिर के पास एक मृत कुआ जो गन्दगी के अम्बार से भरा है और वह दलदल का रूप ले चुका है। उसके आगे ही एक यात्री प्रतीक्षालय भी विधायक निधि से बना हुआ है। जिसके पीछे वाली भूमि सर्वे क्र. 544/1 की कुल भूमि 2.45 हेक्टर थी। उक्त पुरी भूमि पारिवारिक विवाद के साथ ईश्वर ने प्राप्त की। उक्त बात से ग्रामवासियों को कोई लेना-देना नहीं है। परंतु यह सही है कि, उक्त भूमि गांव में होकर अगर एक बार ईश्वर चौहान इस जमीन को टुकुडो-टुकड़ों में भी बेचने की सोचे तो उसके पास इतने करोड़ रुपए आ जाए कि, शायद इतने रुपए देखकर एक बार बेहोश भी हो जाए या यूं कहे की, रात-रात भर नींद भी न आए।

यहां ग्रामवासियों की कहने की बात यह है कि, इतनी संपत्ति होने के बाद भी सार्वजनिक कूप, जो की सड़क से सट्टा होकर मृत है जो गंदगी से भरा है। वही वर्षों से स्थित रोग्या देवी जो रोगों को हरती है उस स्थान को भी ईश्वर चौहान ने अधिकारियों से दलाल के माध्यम से मिलकर व अर्थ लाभ देकर अपने निजी हक की भूमि में दर्ज करवाने का एक घर्षित प्रयास किया है। जिसका विरोध एक तरफा होकर पूरे ग्रामवासी ईश्वर चौहान की निंदा कर रहे हैं।

बात यह है कि, ईश्वर चौहान ने सर्वे क्रमांक 544/1 कुल भूमि 2.45 हेक्टेयर जिसमें से फ्रंट की बजाना व देवगढ़ मार्ग की 25 आरा भूमि का व्यवसायिक डायवर्सन करवाकर दुकानें बनाई है, तथा दुकान के पिछे कमरे निकाल कर वाटिका बनाई है, जिसका सर्वे नं. 544/2 है। तय है उक्त दुकानो व वाटिका के पीछे हिस्से में बाकी की 2.20 हेक्टेयर भूमि है लेकिन व्यवसायिक डायवर्सन भूमि के आगे पीडब्ल्यूडी एवं शासकीय भूमि 540 व 642 सर्वे नं. की भूमि है। जिसमें पीडब्ल्यूडी की सड़क, मृत कूप व यात्री प्रतीक्षालय है। पूरे मामले में यह सामने आया कि, 2023 में स्थानीय करीब 25 से 30 रहवासियों ने नक्शा सुधार हेतु कलेक्टर झाबुआ को एवं थांदला अनुविभागीय अधिकारी राजस्व में वाद प्रस्तुत भी किया था। जिसके साथ ग्राम पंचायत से लेकर, पीडब्ल्यूडी विभाग जनपद थांदला, नायब तहसीलदार खवासा, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कलेक्टर आदि कार्यालयो से प्रकरण के संबंध में कई पत्राचार आदेश हुए एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा 25 मई 2023 को पंचनामा भी बनाया गया। जीसमें कपड़ा नक्शा में जो भूमि 540 व 642 सर्वे नं. की शासकीय भूमि है उस भूमि का हिस्सा ईश्वर चौहान वाली निजी भूमि 544/1 व 544/2 डिजिटल नक्शे में त्रुटिवश दिखाई जा रही है। जिसमें नक्शा सुधार की बात भी दर्शाई गई है। जिसके बाद खवासा के तात्कालीक नायब तहसीलदार पलकेश परमार ने भी पत्र क्रमांक 1056/2023 में रोग्या देवी मंदिर, सार्वजनिक कूप व यात्री प्रतीक्षालय को शासकीय भूमि में होना बताया।

उक्त प्रतिलिपि नायब तहसीलदार द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत थांदला व अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को प्रेषित किया। वहीं अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग उप संभाग पेटलावद नें पत्र क्रमांक 818/2024 दिनांक 1 अगस्त को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद थांदला को आदेश किया और बताया कि, 26 जुलाई 2024 को ग्राम खवासा स्थित सार्वजनिक कुआ का निरीक्षण किया गया। उक्त कुआं मार्ग के शोल्डर को छोड़कर स्थित है एवं कूप की प्रोटेक्शन वाल उचित हाइट पर निर्मित है। ग्राम पंचायत में स्थित होने के कारण मृत कूप को बंद करवाना ईनके क्षेत्राधिकार में है। इसलिए ग्राम पंचायत से उक्त कूप को मिट्टी या मोरम से भराव कर बंद करवाया जाना उचित होगा। उक्त सारी प्रक्रिया के बाद न ही ग्राम पंचायत द्वारा मृत कूप का भराव किया गया, न ही नक्शे में सुधार किया गया।

मंदिर के साईट से देवगढ़ मार्ग व मंदिर के पिछे भी इस मार्ग पर बनी ईश्वर चौहान की दुकाने।

मृत कुप से सट्टा बाजना मार्ग पर प्राचिन रोग्यादेवी मंदिर।

तात्कालिक नायब तहसीलदार पलकेश परमार ने किया ग्राम में बड़े विवाद को उत्पन्न

कहने को तो तात्कालिक खवासा के नायक तहसीलदार उर्फ वर्तमान में मेघनगर प्रभारी तहसीलदार पलकेश परमार की विवादित कार्य प्रणाली अक्सर चर्चा का विषय रही है व समाचार पत्रों की सुर्खियां भी बनी है। लेकिन खवासा के तत्कालिक नायब तहसीलदार परमार खवासा से जाते वक्त भी खवासा में बड़े विवाद को उत्पन्न कर गए है और मामला न्यायालय तक भी पहुंचा है।

मामले में यह कि, जिस 540 व 642 सर्वे नं. भूमि शासकीय है व पूर्व नक्शा अनुसार रोग्या देवी मंदिर, यात्री प्रतीक्षालय व मृत कूप को शासकीय भूमि में होना बताकर 15 दिसंबर 2024 को पत्र क्रमांक 1056 वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित किया। उसी तात्कालिक नायब तहसीलदार पलकेश परमार ने ही नक्शा सुधार करने के बजाय ईश्वर चौहान द्वारा पुत्र-पुत्री के मध्य समान बटवारा का एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। जिसमें नायब तहसीलदार पलकेश परमार ने ईश्वर चौहान के पुत्र देवांशु, प्रभांशु व पुत्री शिवांगी के मध्य 544/1 व 2 में बटवारा किया।

उक्त बंटवारे में व्यावसायिक डायवर्सन वाली ईश्वर चौहान की 25 आरा भूमि जिसमें अपने आगे के अंतिम हिस्से तक अपनी दुकानें बनाकर किराए से दे चुका है। उक्त भूमि के आगे वाली 540 व 642 वाली शासकीय भूमि जिस पर बाजना मार्ग व देवगढ़ मार्ग होकर विशेष रूप से रोग्या देवी मंदिर, सार्वजनिक मृत कूप, व यात्री प्रतीक्षालय स्थित वाली भूमि भी करीब 20 आरा अधिक भूमि 14 अक्टूबर 2024 को नक्शे में ईश्वर चौहान की निजी भूमि में बंटवारे के दौरान पुनः दर्शाई गई है। जिस पर ग्रामवासी आक्रोशित होकर पूरा गांव एक तरफ व दूसरी तरफ ईश्वर चौहान के साथ पलकेश परमार की दोहरी कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है।

ईश्वर चौहान की दुकान के आगे बाजना मार्ग पर यात्री प्रतिक्षालय व पिछे बनी ईश्वर चौहान की दुकाने।

न्यायालय में वाद प्रस्तुत

जिसके विरोध में ग्राम के हित में ग्राम के पटेल हीरालाल लालचंद पटेल, कांतिलाल रणछोड़ डेरिया, रामचंद्र पुना पटेल, नरसिंह रणछोड़ दरबोडिया ने मान्य न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 थान्दला में 7 के विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया। जिसमें क्रमांक (1) पर ईश्वर लाल रामचंद्र चौहान। (2) देवांशु ईश्वर चौहान। (3) प्रभांशु ईश्वर चौहान। (4) शिवांगी चौहान (5) पलकेश परमार तात्कालिक नायब तहसीलदार खवासा। (6) अनुविभागीय अधिकारी पीडब्ल्यूडी पेटलावद। (7) मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर झाबुआ प्रतिवादीगण के विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया है।

उक्त वाद प्रस्तुत में प्रतिवादी (5) तात्कालिक नायक तहसीलदार जिन्हें पूरे प्रकरण से अवगत होकर जिस भूमि को शासकीय भूमि स्वयं के आदेश में दर्शाई गई थी। उक्त भूमि वर्तमान में 540 व 642 सर्वे नं. की शासकीय भूमि की भूमि में से करीब 20 आरा जमीन जिस पर मंदिर,कूप व यात्री प्रतीक्षालय भी स्थित है। तथा व्यावसायिक डायवर्सन वाली ईश्वर चौहान की निजी भूमि 544/2 पर बनी दुकानों के आगे वाली शासकीय भूमि में से ईश्वर चौहान की 544/1 व 2 सर्वे नंबर वाली भूमि में नक्शे में दर्शाकर अपना हित प्रभावित किया है। तथा प्रतिवादी क्रमांक 6 द्वारा निर्मित रोड का अस्तित्व भी नक्शे में से समाप्त कर दिया है और उनका हित भी प्रभावित किया हैं वाद में प्रस्तुत किया गया है। अब देखना है कि उक्तवाद में न्यायालय से क्या आदेश जारी होता है।

ग्रामीणों का यह कहना...

माही की गूंज के माध्यम से खवासा के ग्रामवासियों व मंदिर समिति का कहना है कि, ईश्वर चौहान एक शिक्षित होकर स्वयं शिक्षक होकर शिक्षा भी प्रदान करता है और उनका नाम भी ईश्वर है। ऐसे में ईश्वर चौहान का स्वयं को अपनी निर्धारित व हक की भूमि पर दुकानें बनाई गई है। उसके आगे वाले संपूर्ण भूमि शासकीय है तथा शासकीय भूमि पर ही मंदिर,कूप व यात्री प्रतीक्षालय है यह सभी जानते हैं और प्रशासन द्वारा भी डिजिटल नक्शे में त्रुटि है,कहा गया है। ऐसे में ईश्वर चौहान स्वयं को अपने में अनैतिक विचार दूर कर नैतिक विचारों को उत्पन्न कर स्वयं, नायब तहसीलदार के बंटवारे आदेश में पुनः त्रुटि की गई है के साथ एक प्रतिवेदन देकर उक्त शासकीय भूमि की यह 20 आरा जमीन शासकीय भूमि में परिवर्तन करने हेतु तथा नक्सा सुधार हेतु प्रस्तुत करना चाहिए। और मंदिर समिति व समस्त ग्रामवासियों के बीच आकर अपनी मानवीयता का परिचय देना चाहिये। साथ ही ग्रामवासियों का कहना है कि, जन्म के साथ मृत्यु भी निश्चित है इसलिये अपने नाम व शिक्षा अनुरूप कार्य करें। न कि, ईश्वर चौहान अपनी अनैतिकता का परिचय देकर पूरे ग्राम को उक्त शासकीय भूमि के चलते अपने विरुद्ध विरोधाभास उत्पन्न न करें। साथ ही ग्रामवासियों ने माही की गूंज में प्रकाशित समाचार के साथ ईश्वर चौहान अपने में सुधार लाकर ग्रामहित की बात सोचकर निर्णय लेंगे। और उनके परिणाम भी सार्थक होंगे यह भी उम्मीद की है।

ओ हो... सरपंच जी तो चल दिए, अब शिवदयाल सिंह उठाएंगे जिले की जिम्मेदारी

सामाजिक पुलिसिंग के चक्कर में जिले की कानून व्यवस्था नौ दिन चले अढ़ाई कोस

माही की गूंज, झाबुआ।

वैसे तो इस आदिवासी बाहुल जिले झाबुआ में कानून व्यवस्था दशकों से चुनौती पूर्ण रही है, लेकिन जिले में आए तत्कालीन पुलिस अधीक्षकों में से कुछ ने ही इस चुनौती को स्वीकार किया है। इस सूची में कई ऐसे पुलिस अधीक्षक रहे है जिन्होने जिले में कानून व्यवस्था को सुचारू करने के लिए अपने नाम की धमक और धौंस अपराधियों में बैठाई थी। वैसे जिले में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक जीआर मीणा ऐसे पुलिस अधीक्षक थे जिन्होने तत्कालीन समय में माछलिया जैसे संवेदनशील क्षेत्र में कानवाई की शुरूआत की थी। कानून व्यवस्था को उस स्तर पर पहुंचाया था कि तबादला होने के बाद भी जिले वासियों ने भोपाल पहुंचकर उनका स्थानांतरण रूकवाने तक की कोशिशें की थी। इसके अलावा उमेश जोगा, आशा माथूर, कृष्णावेणी देशावतु और इन जैसे पुलिस अधीक्षकों के नाम हमेशा याद किए जाते रहेंगे। जिन्होने जिले की बिगड़ी कानून व्यवस्था को सुधारने के भरशक प्रयास किए थे, इन प्रयासों में वे काफी हदतक कामयाब भी रहे थे, लेकिन समयावधि की बाध्यता और तबादला निती के कारण हर किसी को यहां से रवानगी लेनी पड़ी। कुछ ने अपना कार्यकाल अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित होकर स्वर्णीम अक्षरों में दर्ज करा लिया तो कुछ ने सामाजिक पुलिसिंग के नाम पर सिर्फ और सिर्फ टाइम पास किया। नित नए हथकंडे अपनाए और तमगे हासिल किए या पदोन्नत होकर जिले से रवानगी ली। इस तरह की फहरिस्त भी काफी लंबी है। किसी पुलिस अधीक्षक ने जिले में पुलिसिंग छोड़कर पौधारोपण अभियान चलाया तो किसी ने सामाजिक पुलिसिंग के नाम पर कई तरह के आडंबर किए। लेकिन इस स्थिति में जिले की कानून व्यवस्था नौ दिन चले अढ़ाई कोस ही साबित हुई।

सोमवार रात पुलिस मुख्यालय से जारी आईपीएस अधिकारियों की तबादला सूची में जिले के पुलिस कप्तान पद्मविलोचन शुक्ल का नाम भी आ ही गया। शुक्ल झाबुआ जिले में पुलिस अधीक्षक पद पर पिछले लगभग डेढ़ वर्षों तक काबिज रहे। इन डेढ़ वर्षों में साहब ने सिर्फ वही काम किए जो उन्हे पद, प्रतिष्ठा और उन्नती दिलाने में सहयोगी साबित हुए। पुलिस अधीक्षक के रूप में उनकी कार्यप्रणाली कम चर्चा में रही, लेकिन सामाजिक पुलिसिंग के मामले में वे इतने आगे थे कि, आदिवासी अंचल में आदिवासी संस्कृति को अपने अलग ही चश्में से देखते और दिखाते रहे। भगोरिया पर्व व आदिवासी संस्कृति पर एक पुस्तक भी प्रकाशित की जो सुर्खियों में सिर्फ विवादों के चलते रही। इसके अलावा आदिवासी परंपराओं में फैर-बदल में भी शुक्ल की काफी रूची देखी गई। हालांकि इनमें से कुछ कार्य उनके सराहनीय कहे जा सकते है, लेकिन कानून व्यवस्था को सुधारने और चुस्त-दुरूस्त करने में एसपी शुक्ल काफी पीछे ही दिखाई दिए है। जिन अपराधिक मामलों में उन्हे सफलता मिली है उसे उन्होने इस तरह से प्रचारित किया मानों जिले की कानून व्यवस्था सबसे चुस्त-दुरूस्त हो। एसपी शुक्ल ने अपराधिक प्रकरणों और गुमशुदगियों जैसे कई मामलों में सफलता तो हासिल की मगर इसके बाद जो उन्होने किया वह बहुत ही हास्यास्पद था। गुमशुदगी में बरामदगी के बाद ऐसे वीडियो ग्राफी करवाई कि तहलका मचा दिया। जिस तरह कोई फिल्म मेकर कोई बायोपिक बनाता है। उसी तर्ज पर साहब की छोटी-छोटी सफलताओं पर वीडियो सूट करवाए गए और फिर उन्हे सोशल मीडिया पर इस तरह वायरल करवाया गया मानों एसपी शुक्ल ही है जो जिले में शक्तिमान के रूप में काम कर रहे हो। यह कोई पहली बार नहीं है, एसपी शुक्ल के पहले भी एक पुलिस अधीक्षक ऐसे ही आए थे जिनकी बॉयोपीक बनने वाली थी, मगर समय ने साथ नहीं दिया और इस बॉयोपिक का भांडा फूट गया। सारे सपने धरे के धरे रह गए। जिन्हे इस बॉयोपिक बनने का कांट्रेक्ट मिला था वे भी सिर्फ हाथ मलते रह गए।

नवागत पुलिस अधीक्षक डॉ. शिवदयाल सिंह

पूर्व पुलिस अधीक्षक डॉ. पदमविलोचन शुक्ल

एसपी शुक्ल की कार्यप्रणाली ऐसी थी कि, वे चटरगुल्ले, चवन्नी छापों और चाटूकार पत्तलकारो को हमेशा अपने आसपास ही रखते थे। या फिर साहब के हर एक कदम की खबर पहले ही चटरगुल्लों तक पहुंचा दी जाती थी, ताकि साहब की फिल्म बन सके। चटरगुल्ले भी एसपी शुक्ल के समक्ष ''जो हुक्म मेरे आका'' कहते हुए हाजिर हो जाया करते थे। सिक्के का दूसरा पहलू यह था कि, एसपी शुक्ल को कभी भी उनकी नाकारात्मक कार्यशैली पर प्रश्नचिन्ह खड़े करने वाले हजम नहीं हुए। कई पत्रकारों ने एसपी शुल्क के खिलाफ अखबारों में खबरें लिखि, कई मोर्चों पर एसपी शुक्ल का खुला विरोध किया, लेकिन पद और पावर का इस्तेमाल शुक्ल अच्छी तरह से समझते थे, अपनी आलोचना उन्हे शायद कभी बर्दास्त ही नहीं हुई। जहां-जहां जब-जब पत्रकारों ने एसपी शुक्ल की आलोचना की तब-तब पत्रकारों की आवाज दबाने का भरसक प्रयास शुक्ल व उनकी टीम द्वारा किया गया। पत्रकारों पर कैमरों से निगरानी और उनके इशुस ढूंढने का काम भी जिले में एसपी शुल्क के पास ही रहा है। पत्रकारों को धौंस, दपट और धमकियां उनकी कार्यप्रणाली में शामिल रही है। अपने पद की गरीमा के विपरीत कई बार उनकी शब्दावली और भाषा में गुंडई प्रवर्ती की झलक साफ दिखाई पड़ती थी। यह सब सिर्फ जिले के उन मीडिया कर्मियों के लिए होता था जो सच को सच लिखने का साहस दिखाते थे, या साहब व सिस्टम की कमियों को उजागर करते थे। क्योंकि, यह भी जिले में स्वतः ही प्रमाणिक है कि जिस तरह की कार्यप्रणाली एसपी शुक्ल ने पत्रकारों के खिलाफ अपनाई थी वो कभी किसी अपराधी, सरगना, माफिया, गुंडों, और जुंआरियों-सटोरियों के खिलाफ जिले में कहीं भी देखने को नहीं मिली। कई पत्रकारों पर अप्रत्यक्ष रूप से मामले दर्ज करवाए गए। विरोध और विद्रोह की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए जिले के हर पत्रकार तक अपने अधिनस्तों को पहुंचाकर दबाने की कोशिशें की गई। मगर सच्चे और अच्छे पत्रकारों के खिलाफ शुक्ल का यह अभियान नाकामयाब ही रहा है।

आदिवासी समाज में जिस तरह से एसपी शुक्ल ने सोशल पुलिसिंग करते हुए कई तरह के अभियान छेड़े थे, क्या अब वे अधर में लटक जाएंगे...? क्योंकि चौक, चौराहों और ग्रामीण इलाकों में एसपी शुक्ल के तबादले के बाद यह चर्चा चल पड़ी है कि ''ओ हो... सरपंच जी तो चल दिए, अब कौन उठाएगा समाज की जिम्मेदारी...?'' कई लोग इस बात को लेकर चटखारे भर रहे है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जिले में यह हर बार की बात है, जब-जब नए अधिकारी आते है वे इस पिछड़े आदिवासी जिले में अपने हिसाब से योजनाएं बनाते है, सामाजिक कार्य करते है और जिले में कई तरह के प्रयोग कर यहां से या तो पदोन्नत होकर निकल जाते है या फिर तबादला निती का शिकार होकर रवानगी ले लेते है। इन आते-जाते अधिकारियों के बीच जिले व यहा की जनता की स्थिति ढाक के तीन पात बनकर रह जाती है।

खैर जो भी हो लेकिन अब जिला फिर से वही देखने जा रहा है ''नई घोड़ी नया दाम''। एसपी शुक्ल यूं तो जिले से ट्रेनिंग के नाम पर रवाना हुए थे लेकिन पुलिस मुख्यालय से निकली तबादला सूची ने उन्हे जिले से पूरी तरह से रवाना कर दिया। अब उनकी जगह जिले को नए एसपी मिले है डॉ. शिव दयाल सिंह। एसपी सिंह वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। प्रदेश के कई जिलों में सेवाएं दे चुके है और कई गंभीर मामलों में सफलता हासिल की है। प्रदेश के खंडवा और देवास में वे अपनी सेवाएं दे चुके है और इन दोनों ही जिलों में सिंह की कार्यप्रणाली काफी सुर्खियों में रही है। सुनने में काफी अच्छा है लेकिन झाबुआ जिले में आगमन के बाद ही स्थितियां साफ होगी कि, एसपी सिंह की कार्यप्रणाली और कार्य योजना किस तरह से इस आदिवासी अंचल में काम करती है। उम्मीदें बहुत है... मगर लंबे समय से सामाजिक पुलिसिंग झेल रहा जिला अब अपराधों के मामले में बहुत आगे है, माफियाओं का खुला राज है, तस्करों की भरमार है, शराब माफियाओं की तूती बोल रही है, नशे का कारोबार आसमान छू रहा है, हर गली-हर नुक्कड़ पर जुआरियों-सटोरियों का बोलबाला है। अब देखना होगा कि, एसपी सिंह अपनी कमान में आए इस जिले को इन सब से कब तक और कैसे मुक्ति दिला पाएंगें...? इन्ही उम्मीदों के साथ माही की गूंज की ओर से एसपी डॉ. शिव दयाल सिंह का आत्मीय अभिनंदन... स्वागत... और शुभकामनाएं....

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा। मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई नंबर- एमपीएचआईएन/2018/76422